अप्रैल-मई-जून-2025, वर्ष 34, अंक 4, 5, 6

उत्तर प्रदेश संदेश

खुशहाल किसान यूपी की पहचान

उत्कर्ष
के
8
वर्ष

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2.86 करोड़+ किसानों को ₹80,000+ करोड़ हस्तांतरित

- गन्ना किसानों को रिकॉर्ड **₹2.80 लाख करोड़+** गन्ना मूल्य का भुगतान
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 58.07 लाख किसानों को **₹47,535.09 करोड़** की क्षतिपूर्ति
- कृषि विकास दर वर्ष 2016-17 में 8.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में **13.7 प्रतिशत** हुई
- पीएम कुसुम योजना में किसानों को **76,189** से अधिक सोलर पम्पों का आवंटन
- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि** योजना लागू
- पीएम किसान मानधन योजना में **2.52 लाख** किसानों को लाभार्थी कार्ड
- 49 जनपदों के **85,710 हेक्टेयर** भूमि में प्राकृतिक खेती
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में **63 हजार से अधिक** किसान लाभान्वित
- वर्ष 2016-2017 में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 5.57 करोड़ मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर लगभग **6.69 करोड़ मीट्रिक टन** हो गया
- कृषि विकास दर वर्ष 2016-17 में 8.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में **13.7 प्रतिशत** हुई
- रबी विपणन वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक **233.99 लाख मी. टन गेहूं की खरीद** कर ₹43,424 करोड़ से अधिक का किसानों को भुगतान
- खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक **456.86 लाख मीट्रिक टन धान क्रय** कर ₹88,746 करोड़ का भुगतान

काम असरदार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश | UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

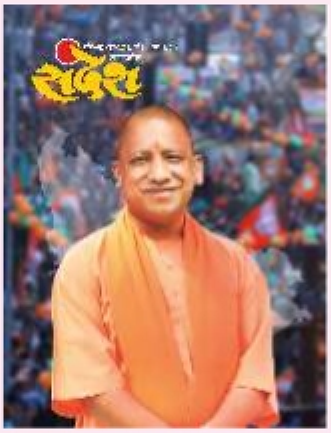

अप्रैल-मई-जून-2025, वर्ष 34, अंक 4, 5, 6

उत्तर प्रदेश
संदेश

संरक्षक एवं मार्गदर्शक :
संजय प्रसाद
प्रमुख सचिव, सूचना
❖
प्रकाशक एवं स्वत्वाधिकारी :
विशाल सिंह
सूचना निदेशक
❖
सम्पादकीय परामर्श :
अंशुमान राम त्रिपाठी
अपर निदेशक, सूचना
❖
सम्पादक
चन्द्र विजय वर्मा
सहायक निदेशक, सूचना
❖
अजय कुमार द्विवेदी
सहयुक्त संपादक
❖
दिनेश कुमार गुप्ता
उपसम्पादक, सूचना

सम्पादकीय संपर्क : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पं. दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर, पार्क रोड, लखनऊ
ईमेल : upsandesh20@gmail.com
दूरभाष कार्यालय : ई.पी.ए.बी.एक्स 0522–2239132–33, 9919874392, 7705800978

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित

भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स की रजिस्ट्री संख्या : 55884 / 91

प्रकाशित सामग्री में विभिन्न लेखकों के दृष्टिकोण एवं विचार से सूचना विभाग की सहमति अनिवार्य नहीं है। लेखों में प्रयुक्त आंकड़े अनन्तिम हो सकते हैं।

इस अंक में

◆ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी : राष्ट्र को समर्पित जीवन 3
-वीरेन्द्र सिंह लोधी

◆ योगी सरकार : आठ साल बेमिसाल 6
-अनिल श्रीवास्तव

◆ उत्कर्ष के आठ वर्ष 11
-डॉ. सौरभ मालवीय

◆ 8 साल के आठ बड़े फैसले 16
-वंदना रावत

◆ कांवड़ यात्रा : आस्था, संयम और त्याग का संगम 19
-विमल किशोर श्रीवास्तव

◆ योगी सरकार भयमुक्त वातावरण बनाने में सफल 24
-सुधा मिश्रा

◆ औद्योगिक विस्तार के आठ साल 27
-प्रज्ञा पांडेय

◆ प्रदेश के कौशल का महाकुम्भ 30
-प्रदीप कुमार गुप्ता

◆ भारत के विकास में गोरखपुर का योगदान सराहनीय : राष्ट्रपति 34
-यशोदा श्रीवास्तव

◆ सर्वोच्च प्राथमिकता, सेहत, सड़क और किसान 37
-चित्रांशी

◆ पारदर्शी पुलिस भर्ती से खिले युवाओं के चेहरे 40
-डॉ. अजय कुमार मिश्रा

◆ उच्च शिक्षा-उच्च गुणवत्ता का संकल्प 44
-सुरेन्द्र अग्निहोत्री

◆ उत्तर प्रदेश : रोजगार प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती.... 48
-रजनीश वैश्य

◆ बेहतर यातायात की धुरी बने एक्सप्रेस-वे 52
-प्रदीप उपाध्याय

◆ आठ साल में बढ़ा धार्मिक पर्यटन 56
-प्रदीप श्रीवास्तव

◆ आत्मनिर्भर होते किसान 59
-अजय श्रीवास्तव

◆ अन्नदाताओं की प्रगति के 8 साल 61
-सियाराम पांडेय 'शांत'

सम्पादकीय

उपलब्धियों के आठ वर्ष

उत्तर प्रदेश, पिछले आठ वर्षों में योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में अभूतपूर्व परिवर्तन का साक्षी बना है। 25 मार्च, 2017 को सत्ता संभालने के बाद से योगी सरकार ने न केवल कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचे में सुधार किया, बल्कि रोजगार सृजन को भी अपनी प्राथमिकता बनाया। ''मिशन रोजगार'' के तहत सरकार ने लाखों युवाओं को नौकरियां प्रदान कीं, जिसने उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था का ''ग्रोथ इंजन'' बनने की दिशा में अग्रसर किया।

योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में रोजगार सृजन को मिशन के रूप में लिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले आठ वर्षों में 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गईं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 95 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इसके अलावा, निजी क्षेत्र में भी निवेश के जरिए लाखों रोजगार सृजित किए गए। 8 वर्षों में प्रदेश को लगभग 45 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए, जिससे नए उद्योगों और स्टार्टअप को बढ़ावा मिला।

कोविड-19 महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तब भी योगी सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को न केवल जारी रखा, बल्कि इसे और पारदर्शी बनाया। ई-अधियाचन पोर्टल की शुरुआत ने चयन प्रक्रिया में तेजी और निष्पक्षता सुनिश्चित की। 2020 से अब तक 35 नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। बेरोजगारी दर, जो 2016 में 18 प्रतिशत थी, अब घटकर 3 प्रतिशत हो गई है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

योगी सरकार ने रोज़गार सृजन में समावेशिता पर विशेष ध्यान दिया। पिछले आठ वर्षों में 1.38 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरियां मिलीं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री 'कन्या सुमंगला योजना' और सामूहिक विवाह जैसी योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया। युवाओं के लिए स्टार्टअप और एमएसएमई योजनाओं को बढ़ावा दिया गया, जिससे स्वरोजगार के लाखों अवसर पैदा हुए। ऑपरेशन कायाकल्प और 'स्कूल चलो अभियान' ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए, जिससे युवाओं को बेहतर कौशल और अवसर प्राप्त हुए।

रोज़गार सृजन के लिए अनुकूल माहौल बनाना योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है। योगी सरकार ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की, जिससे कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, अपराधों में भारी कमी आई और 2 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती ने सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत किया। 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरों की स्थापना ने निगरानी तंत्र को और भी सशक्त किया गया।

इस बेहतर माहौल का परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। **13 एक्सप्रेस-वे** और **8 शहरों** में मेट्रो जैसी परियोजनाओं ने बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े। योगी सरकार ने 2029 तक उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए सरकार ग्रामीण रोज़गार, कौशल विकास और निजी क्षेत्र में उच्च-गुणवत्ता वाली नौकरियों पर ध्यान दे रही है। ''सेवा, सुरक्षा और सुशासन'' के मंत्र के साथ योगी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और पारदर्शी प्रशासन से किसी राज्य का कायाकल्प संभव है।

सम्पादक

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी : राष्ट्र को समर्पित जीवन

–वीरेन्द्र सिंह लोधी

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी महान शिक्षाविद्, गंभीर चिन्तक एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सांस्कृतिक चेतना को समर्पित था। वह केवल राजनेता नहीं, अपितु भारत माँ के सपूत थे। उनकी दूरदर्शिता, निर्भीकता एवं प्रतिबद्धता आज भी प्रेरणास्रोत बनी हुई है। वह कहते थे– "राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानना चाहिए।"

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई, 1901 को कलकत्ता में हुआ था। उनका परिवार धर्मपरायण था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उनके संपूर्ण जीवन पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति थे।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात वह वर्ष 1923 में सेनेट के सदस्य बने। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1924 में उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। कुछ समय पश्चात वर्ष 1926 में वह इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने वर्ष 1927 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। वह अत्यंत परिश्रमी थे इसलिए निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। वह मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए। उन्होंने वर्ष 1938 तक कुलपति का कार्यभार संभाला। अपने कार्यकाल में उन्होंने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। इस समयावधि में उन्होंने 'कोर्ट एंड काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर' तथा इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के सक्रिय सदस्य के रूप में भी उल्लेखनीय कार्य किए। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राजनीतिक जीवन कांग्रेस से प्रारंभ हुआ था। उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में बंगाल विधान परिषद का सदस्य चुना गया था। परन्तु कांग्रेस ने विधायिका का बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया। इसके कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। तदुपरांत उन्होंने स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा एवं विजय प्राप्त की।

उन्हें वर्ष 1943 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। उन्होंने वर्ष 1946 तक यह कार्यभार संभाला। देश की स्वतंत्रता के पश्चात प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया। उन्हें उद्योग एवं

आपूर्ति मंत्री बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से मतभेद के कारण उन्होंने अपनी दिशा परिवर्तित कर ली। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के मध्य हुए समझौते के पश्चात् 6 अप्रैल, 1950 को मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। उनका झुकाव राष्ट्रीय सेवक संघ की ओर हो गया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजनीति के माध्यम से जनसेवा करने के प्रबल पक्षधर थे। वह मानते थे कि राजनीति के माध्यम से समाज के अन्तिम पायदान तक पहुंचकर लोगों का कल्याण किया जा सकता है। उन्होंने संघ की राजनीतिक शाखा बनाने के लिए हिंदू महासभा छोड़ दी थी। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी अर्थात् माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर से भेंट कर इसके निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में दिल्ली के कन्या माध्यमिक विद्यालय में आयोजित सम्मेलन में भारतीय जनसंघ के गठन की घोषणा की। इस प्रकार 21 अक्टूबर, 1951 को भारतीय जनसंघ का गठन किया। सम्मेलन में आयताकार भगवा ध्वज स्वीकृत हुआ, जिस पर अंकित दीपक को चुनाव चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया, इसके साथ ही लोकसभा चुनाव का घोषणा–पत्र भी स्वीकृत किया गया। यहीं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीति में अप्रत्यक्ष रूप से पदार्पण हुआ। इसका श्रेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ही जाता है।

वर्ष 1951–52 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के तीन प्रत्याशियों ने विजय प्राप्त की, जिनमें डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी सम्मिलित थे। इसके पश्चात उन्होंने 32 लोकसभा एवं 10 राज्यसभा सांसदों के सहयोग से नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। वे देश की अखंडता एवं कश्मीर के विलय के प्रबल समर्थक थे। अनुच्छेदों या धारा 370 के प्रावधानों को हटाने के लिए भारतीय जनसंघ ने हिन्दू महासभा एवं रामराज्य परिषद के साथ मिलकर सत्याग्रह आरंभ किया।

वह जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेदों या धारा–370 समाप्त करके इसे भारत का अभिन्न अंग बनाने के इच्छुक थे। उन्होंने संसद में दिए अपने भाषण में धारा–370 को समाप्त करने का स्वर मुखर किया। उन्होंने अगस्त 1952 में जम्मू कश्मीर में आयोजित विशाल रैली में कहा– ''या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन बलिदान कर दूंगा।''

अपने इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए उन्होंने वर्ष 1953 में बिना परमिट लिए जम्मू–कश्मीर की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। 11 मई, 1953 को उन्हें परमिट सिस्टम का उल्लंघन करके कश्मीर में प्रवेश करते समय गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पश्चात् विषम परिस्थितियों में 23 जून, 1953 को उनका निधन हो गया।

अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर उनकी माता योगमाया देवी ने कहा था–

''मेरे पुत्र की मृत्यु भारत माता के पुत्र की मृत्यु है।''

देश की एकता एवं अखंडता के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर देने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के

विचार एवं सिद्धांत प्रेरणादायी हैं। उन्होंने कश्मीर के संबंध में नारा दिया था– “नहीं चलेगा एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान”।

उनका यह विचार आज भी देश की एकता का मूल मंत्र है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना था कि वास्तविक राष्ट्रीय प्रगति धार्मिक शिक्षाओं का उल्लंघन करके नहीं, अपितु धार्मिक शिक्षाओं को अधिक दृढ़ता से अपनाने से प्राप्त की जा सकती है। वह सांस्कृतिक एकता पर भी विशेष बल देते थे। उन्होंने कहा था– ”यदि भारत की स्वतंत्रता को सारपूर्ण बनाना है, तो इसे भारत की संस्कृति के मूल्यों और आधारभूत तत्वों को ठीक प्रकार से समझने और इसके प्रचार एवं प्रसार में मददगार बनना पड़ेगा। जो भी राष्ट्र अपनी पुरातन उपलब्धियों से गौरव महसूस नहीं करता या प्रेरणा नहीं लेता, वह कभी भी न तो अपने वर्तमान को निर्मित कर सकता है और न ही कभी भी अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार कर सकता है। कोई भी कमजोर राष्ट्र कभी भी महानता की ओर अग्रसर नहीं हो सकता।”

वह कहते थे– “आप जो भी काम करते हैं, इसे गंभीरता से अच्छी तरह करें। इसे कभी भी आधा–अधूरा नहीं करें। तब तक स्वयं को संतुष्ट न समझें जब तक कि आप इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ न दे दें। अनुशासन और गतिशीलता की आदतों को विकसित करें। अपने दृढ़ विश्वास को न टूटने दें।”

> **डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी महान शिक्षाविद्, गंभीर चिन्तक एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सांस्कृतिक चेतना को समर्पित था। वह केवल एक राजनेता नहीं थे, अपितु भारत माँ के सपूत थे। उनकी दूरदर्शिता, निर्भीकता एवं प्रतिबद्धता आज भी प्रेरणास्रोत बनी हुई है। वह कहते थे– ”राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानना चाहिए।”**

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह कहते हैं कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समर्पण, शिक्षा और विकास के नवीन विचारों का अद्भुत संगम था। बंगाल की रक्षा के लिए संघर्ष और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए हर भारतवासी ऋणी है।

डॉ. मुखर्जी जी की विद्वता और ज्ञान सम्पदा का लोहा उनके राजनीतिक विरोधी भी मानते थे। वह जानते थे कि उस समय की सरकार जिन विचारों और नीतियों पर चल रही थी, उससे देश की समस्याओं का निराकरण सम्भव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने राष्ट्रहित में सत्ता सुख को त्याग कर लंबे संघर्ष का जटिल मार्ग चुना। डॉ.मुखर्जी का मानना था कि एक राष्ट्र का उज्ज्वल भविष्य उसकी अपनी मूल संस्कृति और चिंतन की मजबूत नींव पर ही संभव है। इसीलिए उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के वैज्ञानिक दृष्टिकोण व वैकल्पिक राजनीतिक सोच देश के सामने रखी। उनके विचार आज देश को हर क्षेत्र में आगे ले जा रहे हैं।

मा. जेपी नड्डा कहते हैं कि एक देश में ‘दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे’ यह केवल उद्घोष नहीं था, अपितु राष्ट्र की एकता के लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का अडिग संकल्प था। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनुच्छेद–370 इतिहास बन चुका है। यह केवल संवैधानिक सुधार नहीं, अपितु डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि है।

डॉ. मुखर्जी जी का जीवन सत्ता नहीं, सिद्धांतों के लिए था। उनके विचार आज भी राष्ट्रवाद की सबसे शुद्धतम अभिव्यक्ति है।

निःसंदेह अखंड भारत के जिस संकल्प के लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था, वह संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज राष्ट्र के नवनिर्माण के साथ साकार हो रहा है। उनके प्रखर विचार, चिंतन एवं सर्वांगीण विकास के लिए मार्गदर्शन गौरवशाली भारत के निर्माण के आधार स्तंभ हैं। ◆

(लेखक : भाजपा से मारहरा (एटा) विधानसभा के विधायक हैं)

मो. : 9627965555

योगी सरकार : आठ साल बेमिसाल

–अनिल श्रीवास्तव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। कुल मिलाकर लगातार आठ साल तक उत्तर प्रदेश में विकास, सेवा, सुरक्षा और सुशासन के संकल्प को साकार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबी लकीर खींच दी है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड भी बना दिया है। हाल ही में प्रयागराज में सफल ऐतिहासिक महाकुंभ का आयोजन कर योगी सरकार ने केवल देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की अलग पहचान बनाई है। यही नहीं, बीते आठ वर्षों में योगी सरकार ने न सिर्फ संगठित अपराध पर शिकंजा कसा है, बल्कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा व अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण पाने में भी सफलता हासिल की है। प्रदेश में सुदृढ़ कानून–व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति लायें। नतीजा सामने है कि यूपी हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य की पहचान रखने वाला उत्तर प्रदेश आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है।

2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली थी तो सामने अनेक चुनौतियां थीं। खासतौर पर कानून–व्यवस्था, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने जैसे बड़े लक्ष्य सामने थे। सीएम योगी ने दृढ़ता से अपने एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए देश–दुनिया में न केवल प्रदेश की छवि बदली बल्कि प्रदेश को उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, जहां तमाम राज्य यूपी की नीतियों का अनुसरण करते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र से लेकर प्रदेश की शासकीय योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करके गरीबों तक लाभ पहुंचाने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले पायदान पर पहुंच चुका है। योगी सरकार की बीते आठ साल की उपलब्धियों पर नजर डालें तो सबसे बड़ी कामयाबी संगठित अपराध को कुचलने की रही है, जिससे न सिर्फ कानून–व्यवस्था में सुधार हुआ है बल्कि आम लोगों के साथ–साथ उद्योगों व कारोबारियों के लिए अनुकूल माहौल बना है। निवेशकों का

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। कुल मिलाकर लगातार आठ साल तक उत्तर प्रदेश में विकास, सेवा, सुरक्षा और सुशासन के संकल्प को साकार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबी लकीर खींच दी है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड भी बना दिया है। हाल ही में प्रयागराज में सफल ऐतिहासिक महाकुंभ का आयोजन कर योगी सरकार ने केवल देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की अलग पहचान बनाई है।

भरोसा बढ़ा है और बड़ी संख्या में देशी–विदेशी निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाएं जमीनी धरातल पर उतारी गई हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश आज निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। कानून–व्यवस्था के मोर्चे पर लगातार दृढ़ता से ध्यान देने का ही नतीजा है कि माफिया राज खत्म हुआ और यूपी की पहचान भयमुक्त प्रदेश की बनी है। एनसीआरबी के आंकड़े भी इस बात के गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधों में कमी हुई है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली, अवैध धर्मांतरण, गोहत्या और नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए लागू किए गए कानूनों से पूरे देश में यूपी को लेकर धारणा ही नहीं बदली है, अपितु कई राज्य इसके नक्शे कदम पर भी हैं। योगी सरकार ने बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया। 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे को साकार करने के लिए शुरू की गई योजनाएं आम आदमी, खास तौर पर गरीबों के जीवन में बदलाव लाने में बेहद कारगर साबित हुई हैं। किसानों के लिए ऋण माफी, बाणसागर और सरयू नहर जैसी सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने के साथ–साथ नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ने स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदली है। खाद्यान्न, गन्ना, आलू, एथेनॉल उत्पादन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, आयकर रिटर्न, जेम पोर्टल खरीद, कौशल विकास, एमएसएमई, पीएम आवास,

सुरेश कुमार खन्ना
सूर्य प्रताप शाही

प्रयागराज की पुण्य भूमि पर महाकुंभ के सफल आयोजन ने एक सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को वैश्विक पटल पर कई गुना अधिक समृद्ध किया है। महाकुंभ के प्रति भारत के गांव–गांव और समाज के हर वर्ग में जबरदस्त उत्साह दिखा, वो चाहे महिलाएं हों या बुजुर्ग, युवा हों या बच्चे। महाकुंभ के दौरान आस्था की डुबकी लगाने को लेकर जो उत्साह और उमंग देखा गया उसकी दूसरी कोई मिसाल मिलना दुर्लभ है। प्रयागराज महाकुंभ में भी 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। खास बात यह रही कि आस्था अर्थव्यवस्था का सशक्त माध्यम बनी। महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया।

उज्ज्वला, स्वामित्व, जन धन, सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा योजना में यूपी नंबर एक है, जो उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करने की योगी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है तो योगी सरकार की उत्कृष्ट नीतियों का परिणाम है कि आज यूपी अर्थव्यवस्था में नंबर 2 का राज्य बन चुका है। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2017 के बाद से राज्य की जीडीपी लगभग दोगुनी होकर 2025 तक +1 ट्रिलियन की ओर बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय भी 2016–17 की तुलना में दोगुने से अधिक बढ़ी है। राष्ट्रीय जीडीपी में यूपी का योगदान 9.2 प्रतिशत हो गया है जो इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में योगी सरकार कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश का बजट आठ लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में योगी सरकार पूरी गंभीरता से प्रयासरत है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने पर खास तौर पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में किए गए करारों को धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलावा डिफेंस कॉरिडोर के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित की जा रही रक्षा उत्पाद इकाइयां तथा उद्योग–धंधों के मामले में पिछड़े माने जाने वाले बुंदेलखंड और पूर्वांचल में भी स्थापित हो रहे नए उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और उसे मजबूत करने में खासे कारगर साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर एक्सप्रेस–वे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हुई है। जल्द ही पूरे देश के एक्सप्रेस–वे में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 55 फीसदी तक

Indian Bank
Lead Sponsor

सपने हो रहे साकार
8.5 लाख+
3.75 लाख+
संविदा पर नौकरी
करोड़+
494 सहायक अध्यापकों

होने जा रही है। इससे भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। बीते आठ वर्षों में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए योगी सरकार द्वारा एक्सप्रेस–वे के साथ–साथ हवाई अड्डों के विस्तार की दिशा में किए गए कार्यों का परिणाम है कि उद्यमियों और कारोबारियों का उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने तक पहुंचना बेहद आसान हो गया है।

बात करें कृषि क्षेत्र की तो बीते आठ वर्षों में कृषि में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। यूपी में कृषि दर 5.1 प्रतिशत से बढ़कर 13.7 प्रतिशत हो गई है। किसानों के कर्ज माफी, सिंचाई क्षमता में वृद्धि से न सिर्फ किसानों को राहत मिली है बल्कि खेती–किसानी की राह भी आसान हुई है। योगी सरकार के आठ वर्ष के कार्यकाल में जहां चीनी उद्योग को संजीवनी मिली है वहीं किसानों को ज्यादा गन्ना भुगतान भी किया गया है। फल व सब्जी उत्पादन में यूपी अव्वल हो गया है। 14 लाख निजी नलकूपों को बिजली दी गई है। 2017 से गेहूं क्रय पर ढाई गुना ज्यादा खर्च किया है। पीएम कुसुम योजना अंतर्गत सोलर पैनल लगाकर लगभग 86 हजार किसानों के जीवन में बदलाव लाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र, नए कृषि विश्वविद्यालय और टेक्नोलॉजी के उपयोग से धान, गेहूं, दलहन और श्री अन्न में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर पहुंच गया है। कृषि उत्पादन और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए योगी सरकार के प्रयास सराहनीय रहे हैं। योगी सरकार का जोर शासकीय योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने पर है। महिलाओं, युवाओं और गरीबों समेत अन्य वर्गों के लिए लागू की गई योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम बढ़ाए गए हैं। खासतौर पर महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने की योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। 1.65 करोड़ गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। इससे भी योगी सरकार की छवि बेहतर हुई है। बिचौलियों का दखल खत्म होने से योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। जनकल्याण से जुड़ी दो दर्जन से अधिक केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में यूपी नंबर वन हो गया है। योगी

श्री नरेन्द्रभाई मोदी
BIKING QUEENS
RIDE FOR WOMEN'S

सरकार के बीते आठ वर्षों में 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाने में जो कामयाबी हासिल हुई है, वो गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के राज्य सरकार के संकल्प का प्रमाण है। प्रयागराज की पुण्य भूमि पर महाकुंभ के सफल आयोजन ने एक सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को वैश्विक पटल पर कई गुना अधिक समृद्ध किया है। महाकुम्भ के प्रति भारत के गांव–गांव और समाज के हर वर्ग में जबरदस्त उत्साह दिखा, वो चाहे महिलाएं हों या बुजुर्ग, युवा हों या बच्चे। महाकुंभ के दौरान आस्था की डुबकी लगाने को लेकर जो उत्साह और उमंग देखा गया उसकी दूसरी कोई मिसाल मिलना दुर्लभ है। **प्रयागराज महाकुम्भ में भी 67 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे।** खास बात यह रही कि आस्था अर्थव्यवस्था का सशक्त माध्यम बनी। महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया। कनेक्टिविटी, सुरक्षा और सुविधाओं के विकास ने पर्यटन को बढ़ावा दिया। महाकुम्भ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे लाखों श्रद्धालु अयोध्या और काशी भी पहुंचे। अयोध्या और काशी में भी आस्था का ज्वार उमड़ा। इससे इन क्षेत्रों में भी स्थानीय कारोबारियों को काफी फायदा हुआ। 45 दिनों तक चले इस भव्य आयोजन ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। प्रयागराज की धरती पर जहां एक ओर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का अथाह जनसैलाब दिखा, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस आयोजन से देश और विशेषकर उत्तर प्रदेश को काफी लाभ हुआ है। महाकुम्भ के दौरान जिस कुशलता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार, रेल मंत्रालय सहित अन्य संबंधित विभागों ने प्रबंधन किया, उसने पूरी दुनिया को विस्मित कर दिया। प्रबंधन और प्लानिंग के क्षेत्र में कार्य करने वाले शोधार्थियों के लिए प्रयागराज महाकुंभ का सफल प्रबंधन, शोध और उत्सुकता का विषय बन गया। यह महाकुम्भ आस्था के साथ अर्थव्यवस्था में भी अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए सदैव याद रखा जाएगा।

योगी सरकार अपने वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। आठ साल का यह सफर न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व का प्रमाण है बल्कि प्रदेश की जनता के विश्वास का भी प्रतीक है, जिसने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। ◆

मो. : 9935097410

उत्कर्ष के आठ वर्ष

–डॉ. सौरभ मालवीय

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने द्वितीय कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। उन्होंने 25 मार्च, 2022 को द्वितीय बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस अवसर पर उन्होंने शपथ लेते हुए कहा था कि "मैं आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।"

योगी आदित्यनाथ अपनी इस शपथ का किस प्रकार हृदय से पालन कर रहे हैं, यह सर्वविदित है। इससे पूर्व उन्होंने प्रथम बार 17 मार्च, 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वह पांच बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। प्रदेश की जनता को उनकी कार्यशैली सर्वोत्तम लगी और उसने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजयी बना दिया अर्थात् 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 273 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार योगी आदित्यनाथ को द्वितीय बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में लगभग साढ़े तीन दशक के पश्चात किसी राजनीतिक दल को पुनः सत्ता में लाने वाले योगी आदित्यनाथ प्रथम राजनेता हैं। शासनकाल में **प्रदेश में आध्यात्मिक गतिविधियों को अत्यंत प्रोत्साहित किया जा रहा है।** महाकुम्भ का सफल आयोजन इस बात का प्रमाण है। महाकुम्भ से पूर्व प्रयागराज के ऐतिहासिक मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण किया गया। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पर्यटन विभाग, स्मार्ट सिटी एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मिलकर यह कार्य संपन्न किया। मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आस्था एवं सुविधा को प्राथमिकता दी। महाकुंभ मेले के दृष्टिगत प्रदेश को हरभरा बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त स्वच्छता पर विशेष बल दिया गया। यातायात सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया। योगी आदित्यनाथ के परिश्रम का परिणाम है कि इस मेले में **50 करोड़** से अधिक लोगों ने स्नान कर पुण्य अर्जित किया। इसके अतिरिक्त राज्य में प्रत्येक वर्ष कांवड़ यात्रा पर यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। यात्रियों के मार्ग में टेंट लगाए जाते हैं। उन पर हेलिकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है। वास्तव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना किसी पूर्वाग्रह एवं भेदभाव के कार्य करते हैं, जिससे लोगों में सरकार के प्रति सकारात्मक संदेश जाता है। उनकी समयावधि में सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों को उतरवा दिया गया।

वास्तव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाज के हित के अनुसार ही सरकार की छवि को सुदृढ़ करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। प्राचीन नगरों को संरक्षित करना

तथा अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर का निर्माण इसके उदाहरण हैं। सरकार नमामि गंगे योजना के अंतर्गत गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल करने पर विशेष बल दे रही है। गंगा का प्रदूषण कम करने के लिए (स्मार्ट गंगा सिटी) परियोजना पर कार्य चल रहा है। योगी सरकार राज्य में पर्यटन विशेषकर धार्मिक पर्यटन को भी प्रोत्साहित कर रही है। राज्य में गो संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में निराश्रित लोगों को आवास देने के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास योजना प्रारम्भ की गई। निर्धन परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आरम्भ की गई। प्रवासी श्रमिकों को आजीविका देने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान प्रारम्भ किया गया। बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आरम्भ की गई। बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन तथा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई। राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना प्रारम्भ की गई। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता नामक योजना आरम्भ की गई। राज्य के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ देने के लिए श्रमिक पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गई। श्रमिकों के भरण पोषण के लिए राज्य में श्रमिक भरण पोषण योजना आरम्भ की गई है। इसके साथ ही राज्य की समृद्धि के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

योगी सरकार ने कृषि क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया है। प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए परम्परागत खेती विकास योजना चलाई जा रही है। खेतों को पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना तथा उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना संचालित की जा रही है। इनके अतिरिक्त बीज ग्राम योजना के अंतर्गत किसानों को धान एवं गेहूं के बीज पर विशेष अनुदान दिया जा रहा है। पारदर्शी किसान सेवा योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को समुचित उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। किसानों को ऋण के बोझ से मुक्त करने के लिए किसान ऋण मोचन योजना प्रारम्भ की गई। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने द्वितीय कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। उन्होंने 25 मार्च, 2022 को द्वितीय बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस अवसर पर उन्होंने शपथ लेते हुए कहा था कि "मैं आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।"

प्रदेश में अनाथ बच्चों को शरण देने के लिए मुख्यमंत्री (बाल सेवा योजना) प्रारम्भ की गई। महिला सशक्तीकरण के लिए भी सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री (कन्या सुमंगला योजना) के अंतर्गत निर्धन परिवारों की पुत्रियों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत पुत्री की शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त लोगों को घर बैठे बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकिंग संवाददाता सखी योजना प्रारम्भ की गई है। इससे जहां लोगों को घर पर बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, वहीं महिलाओं को भी रोजगार प्राप्त हुआ है।

प्रदेश में अनेक पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें **उत्तर प्रदेश पेंशन योजना**, विधवा पेंशन योजना तथा उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पेंशन योजना सम्मिलित हैं। सरकार लड़कियों और दिव्यांगों के विवाह के लिए अनुदान प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत कमजोर परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के विवाह लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य कर रही है। प्रदेश में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों एवं उनके नये भवनों की स्थापना की जा रही है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। उच्च शिक्षा में 119 राजकीय महाविद्यालयों में ई–लर्निंग पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं तथा 87 राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था की गई है तथा प्रदेश के 27 विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ 111 अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 26 नये सरकारी पॉलिटेक्निक स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 24 निर्माणाधीन हैं।

सरकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले और विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाने का भी निर्णय लिया है। एक जिला एक खेल योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगी सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। प्रदेश के सभी 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ एटीएम लगाए जा रहे हैं। **प्रदेश के 65 जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय चल रहे हैं।** गोरखपुर और रायबरेली में एम्स चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्रदेश के करोड़ों लोगों को **पांच लाख** रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत लाया गया है। योगी सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर है। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेफ सिटी योजना प्रारम्भ की गई है। विद्युत क्षेत्र में भी योगी सरकार उत्कृष्ट कार्य किया है। परिवहन के क्षेत्र में भी सरकार ने सराहनीय कार्य किए हैं।

निःसंदेह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के पश्चात प्रदेश में विकास कार्यों की गंगा बहा दी है। आज उत्तर प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में देशभर में अपनी पृथक पहचान स्थापित की है। कृषि उत्पादों में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश लगातार देश में प्रथम स्थान पर रहा। गन्ना मूल्य का भुगतान कर उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी रहा। खाद्यान्न गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला एवं दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम रहा। तिलहन उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। किसानों को देय अनुदान को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। उत्तर प्रदेश किसानों के लिए बाजार को व्यापक बनाने हेतु मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का प्रथम राज्य है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में भी उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा।

लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम रहा। इसी प्रकार उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी रहा। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत लोगों को लाभान्वित कर देश में द्वितीय स्थान पर रहा।

निर्माण कार्यों में भी उत्तर प्रदेश किसी से पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 40 लाख से अधिक निर्माण एवं निर्माण कार्यों को स्वीकृति देकर उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा। इसके अतिरिक्त **उत्तर प्रदेश पांच एक्सप्रेस–वे का एक साथ** निर्माण कर अग्रणी रहा। **साथ ही 30 नये मेडिकल**

120th
Foundation Day
120 वां
स्थापना दिवस
21 दिसम्बर 2024

कॉलेजों का निर्माण करके भी उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। उत्तर प्रदेश आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के आधार कार्ड सीडिंग, आवास चयन, प्रथम द्वितीय, तृतीय किस्त जारी करने और आवास निर्माण आदि के प्रदर्शन में भी अग्रणी रहा। उत्तर प्रदेश दो करोड़ 61 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करके भी देश में प्रथम स्थान पर रहा है।

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक कोरोना जांच एवं टीकाकरण करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश कोरोना काल में सर्वाधिक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित करने वाला राज्य रहा। उत्तर प्रदेश कोरोना काल में दूसरे राज्यों से घर वापस आने वाले कामगारों तथा असंगठित श्रमिकों, फेरी वालों, रिक्शा चालकों, कुलियों, पल्लेदारों आदि को निःशुल्क खाद्यान्न एवं भरण–पोषण भत्ता देने वाला अग्रणी राज्य है। नोएडा में उत्तर भारत के प्रथम डेटा सेंटर की स्थापना हुई।

औद्योगिकीकरण के लिए भूमि उपलब्धता एवं आवंटन में भी उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष राज्यों में सम्मिलित है। साथ ही उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में देश में अग्रणी रहा। सैनिटाइजर और मास्क उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सरकारी नौकरियां और रोजगार देने वाला राज्य है।

उत्तर प्रदेश ने 'एक जनपद–एक उत्पाद' को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उत्तर प्रदेश सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने वाला उत्तर भारत का प्रथम राज्य है। उत्तर प्रदेश ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 101 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित कर डेढ़ करोड़ श्रमिकों को रोजगार दिया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य है।

उत्तर प्रदेश ने 'एक जनपद–एक योजना' को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने वाला उत्तर भारत का प्रथम राज्य है। उत्तर प्रदेश ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 101 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित कर डेढ़ करोड़ श्रमिकों को रोजगार दिया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक सात करोड़ दो लाख खाते खोले गए। उत्तर प्रदेश अटल पेंशन योजना के अंतर्गत **36 लाख 60 हजार 615** लोगों को लाभान्वित कर देश में अग्रणी रहा। उत्तर प्रदेश ई–मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से सर्वाधिक सरकारी खरीददारी करने में अग्रणी रहा। उत्तर प्रदेश ई–चालान व्यवस्था लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। ई– प्रोसिक्यूशन प्रणाली लागू करने में भी यह राज्य अग्रणी है। उत्तर प्रदेश ने 37.21 करोड़ पौधारोपण करके रिकॉर्ड स्थापित किया। उत्तर प्रदेश मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला प्रथम राज्य है। उत्तर प्रदेश सूचनाओं के आदान–प्रदान एवं पारदर्शिता में भी अग्रणी है।

उत्कृष्ट कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश को देश में सर्वाधिक प्रदर्शन का पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को दो करोड़ रुपये का कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश को पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ई–टेंडरिंग प्रणाली में उत्तर प्रदेश ने सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए अवार्ड प्राप्त किया।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी बसों में पैनिक बटन एवं सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य बना। उत्तर प्रदेश में अविरल और निर्मल गंगा के प्रति जन जागरूकता के लिए प्रथम बार गंगा यात्रा का आयोजन किया गया। अयोध्या दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश ने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। भाजपा अपने घोषणा–पत्र में जनता से किए वादों को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ◆

मो. : 8750820740

8 साल के आठ बड़े फैसले

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर बदला प्रदेश का परसेप्शन

–वंदना रावत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 साल के कार्यकाल में अब तक कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिन्होंने राज्य की दशा और दिशा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लव जिहाद के खिलाफ कानून हो या फिर नकल और पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून, महिलाओं के सम्मान और स्वावलंबन को सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति की पहल हो या फिर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का निर्णय इन सभी के दीर्घ प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। इन निर्णयों ने यह भी साबित किया कि उत्तर प्रदेश में वो सरकार काबिज है, जिसके पास नीयत भी है और नीतियां भी। योगी सरकार के 8 साल में 8 महत्वपूर्ण निर्णयों पर एक नजर...

योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाकर जबरन धर्मांतरण पर कसी नकेल

1. लव जिहाद के खिलाफ बनाया कानून

सीएम योगी की पहल पर नवंबर 2020 में ''उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम'' लागू हुआ। इस कानून के तहत जबरन या छल से धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। पहले साल में ही 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए। यह कानून महिलाओं की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी।

मिशन शक्ति के जरिए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को किया गया सुनिश्चित

2. मिशन शक्ति की शुरुआत

अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ ''मिशन शक्ति'' अभियान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर केंद्रित है। इसके तहत एंटी–रोमियो स्क्वाड ने छेड़छाड़ के 32 हजार से अधिक मामलों में कार्रवाई की। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 22 लाख से ज्यादा बेटियों को आर्थिक मदद दी गई। 112 और 181 जैसी हेल्पलाइन ने आपात स्थिति में सहायता प्रदान की।

3. किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली

किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार

ने विगत वर्ष उत्तर प्रदेश के निजी नलकूप उपभोक्ताओं को एक अप्रैल 2024 से बिजली बिल में 100 प्रतिशत छूट का लाभ देने का निर्णय लिया। इस निर्णय को पावर कॉर्पोरेशन ने विधिवत लागू किया। सिंचाई सुविधा के लिए 4 लाख से ज्यादा निजी नलकूपों का संयोजन किया गया। किसानों को विद्युत आपूर्ति के लिए 3 हजार से अधिक ग्रामीण फीडर अलग किए गए। निजी नलकूप कनेक्शन देने में डार्क जोन में लगे प्रतिबंध हटाने से लाखों किसान लाभान्वित हुए।

4. सभी राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए चिकित्सा सुविधा फ्री

योगी सरकार ने 2022 में उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स व उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिलने लगा। इसके तहत, राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के स्टेट हेल्थ कार्ड बनाए गए। स्टेट हेल्थ कार्ड में कर्मचारियों व उनके आश्रितों से संबंधित सभी डाटा संरक्षित रखने की सुविधा है। इस हेल्थ कार्ड को दिखाकर वे किसी भी सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त कर पा रहे हैं। योजना के तहत लाभार्थियों के इलाज के लिए प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में प्रचलित दरें ही मान्य हैं।

5. नकल और पेपर लीक पर बनाया सख्त कानून

परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने और नकल के खिलाफ भी योगी सरकार ने 2024 में सख्त कानून बनाकर मिसाल पेश की। पेपर लीक कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी (नकल) पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद की सजा का प्राविधान है और पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम एक करोड़ रुपए के जुर्माने का प्राविधान है। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई संगठित अपराध करता है, जिसमें परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, सेवाप्रदाता या कोई अन्य संस्थान शामिल है तो उन्हें कम से कम 5 साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

खुशहाल किसान, यूपी की पहचान

6. उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन

योगी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 'उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण' के गठन को मंजूरी दे दी है। इस प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 'उत्तर प्रदेश जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली 2025' को प्रख्यापित किया गया है। देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना सहित कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग मौजूद हैं। जलमार्गों के जरिए परिवहन को किफायती और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इस प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है। सरकार का मानना है कि जल परिवहन प्रणाली विकसित होने से यातायात के अन्य साधनों पर दबाव कम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

योगी सरकार ने 2022 में उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स व उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिलने लगा। इसके तहत, राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के स्टेट हेल्थ कार्ड बनाए गए। स्टेट हेल्थ कार्ड में कर्मचारियों व उनके आश्रितों से संबंधित सभी डाटा संरक्षित रखने की सुविधा है। इस हेल्थ कार्ड को दिखाकर वे किसी भी सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त कर पा रहे हैं। योजना के तहत लाभार्थियों के इलाज के लिए प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में प्रचलित दरें ही मान्य हैं।

7. एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनाने का निर्णय

योगी सरकार ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीआर) की तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाकों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र (एस.सी.आर.) के गठन को मंजूरी दी है। इसे उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए योगी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। लखनऊ और आसपास के 6 जिलों के कुल 27826 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

8. 47 वर्षों के बाद एक और औद्योगिक शहर के गठन का फैसला

ऐतिहासिक निर्णयों की कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) की तर्ज पर बुंदेलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के गठन की अधिसूचना को भी 2023 में मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश में इससे पहले 1976 में नोएडा नाम से एक नए शहर के गठन का निर्णय लिया गया था। 47 वर्षों के बाद एक और नए नगर की स्थापना का फैसला किया गया। झांसी जिले के 33 गांवों को शामिल करके बीडा का गठन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक निर्णय से बुन्देलखण्ड के बहुआयामी विकास को रफ्तार मिलेगी। ◆

मो. : 8076633206

कांवड़ यात्रा : आस्था, संयम और त्याग का संगम

–विमल किशोर श्रीवास्तव

भारत एक धार्मिक आस्था प्रधान देश है तथा सनातन धर्म की गंगोत्री है, जहाँ आस्था, भक्ति और तप की धाराएँ समय के साथ और भी प्रबल होती रहतीं हैं। जहाँ विविध तीर्थ यात्राएँ जनमानस की श्रद्धा का केंद्र हैं। इन्हीं में से एक है कांवड़ यात्रा, एक ऐसी अनूठी यात्रा, जो केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन, आत्मा और श्रद्धा से की जाती है। जो हर वर्ष सावन माह में आयोजित होती है। सावन मास के पावन अवसर पर जब लाखों शिवभक्त कंधे पर गंगाजल लिए हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख और अन्य तीर्थों से अपने गांव–नगर के शिवलिंग तक नंगे पाँव यात्रा करते हैं, वे गंगाजल लाने हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख या अन्य पवित्र स्थलों की ओर पैदल यात्रा करते हैं और उसे अपने क्षेत्र के शिवालयों में चढ़ाते हैं। यह दृश्य केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि **सांस्कृतिक–जागरण और धार्मिक आंदोलन** का रूप ले लेता है। कांवड़िया श्रद्धालु गंगा के तट से जल भरकर अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में “जलाभिषेक” करते हैं। यह जल लाने की यात्रा ही “कांवड़ यात्रा” कहलाती है।

कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, संयम, त्याग और सेवा का संगम है। वर्तमान युग में जहाँ भौतिकता, भाग–दौड़ और तनाव की अधिकता है, वहाँ कांवड़ यात्रा जैसे आध्यात्मिक उपक्रम आत्मशुद्धि, आत्मनियंत्रण और परमात्मा से संबंध जोड़ने का सशक्त माध्यम हैं। यह यात्रा “एकांत में नहीं, जनसमूह के बीच ईश्वर की खोज” का नाम है।

कांवड़ का अर्थ है– दो सिरों पर लटकती जलकलशों वाली वह लकड़ी, जो भक्त अपने कंधे पर लेकर यात्रा करते हैं।

“भोले के नाम पे चला है कारवां, कांधे पे गंगाजल, दिल में है विश्वास का आसमान...”

कांवड़ यात्रा का उल्लेख पुराणों और लोककथाओं में मिलता है। शिवपुराण के अनुसार, जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष प्रकट हुआ, तब समस्त देवताओं और असुरों को बचाने हेतु भगवान शंकर ने उसे अपने कंठ में

धारण किया। उनके इस आत्मबलिदान को सहन करने हेतु गंगाजल चढ़ाकर उन्हें शीतलता प्रदान की गई। तब से यह परम्परा प्रचलित हुई कि श्रावण मास में भगवान शिव को पवित्र गंगाजल चढ़ाया जाता है।

कांवड़ यात्रा केवल धर्म का उत्सव नहीं, यह भारतीय समाज की सहिष्णुता, सामूहिक चेतना और अनुशासन का आदर्श उदाहरण है। इस यात्रा में हर जाति, हर वर्ग, हर उम्र का भक्त शामिल होता है। गाँव–गाँव से युवा टोली बनाकर निकलते हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, महिलाएँ मंगलगीत गाकर विदा करती हैं और नागरिक सेवा शिविर लगाकर पथिकों का स्वागत करते हैं।

यह यात्रा न केवल भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक समरसता, अनुशासन और संयम का भी संदेश देती है। कांवड़िए समूहों में यात्रा करते हैं, भजन–कीर्तन गाते हुए आगे बढ़ते हैं। कांवड़िये संकल्पपूर्वक नियमों का पालन करते हैं– शाकाहार, ब्रह्मचर्य, सत्य का पालन, असत्य से परहेज, मधुर व्यवहार और निरंतर जप–कीर्तन।

कांवड़ के रास्ते में गांव–गांव, नगर–नगर सेवा शिविर, भंडारे, शीतल जल वितरण, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र आदि इस यात्रा को आस्था का उत्सव बना देते हैं। यात्रा मार्ग पर "बोल बम", "हर हर महादेव", "जय शंभू" के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठता है।

कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, संयम, त्याग और सेवा का संगम है। वर्तमान युग में जहाँ भौतिकता, भाग–दौड़ और तनाव की अधिकता है, वहाँ कांवड़ यात्रा जैसे आध्यात्मिक उपक्रम आत्मशुद्धि, आत्मनियंत्रण और परमात्मा से संबंध जोड़ने का सशक्त माध्यम हैं। यह यात्रा "एकांत में नहीं, जनसमूह के बीच ईश्वर की खोज" का नाम है।

हर वर्ष कांवड़ यात्रा में उत्तर प्रदेश से लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं, इनमें विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश (जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, गाजियाबाद आदि) में कांवड़ यात्रा का सबसे व्यापक रूप देखने को मिलता है। इन शहरों से तो इस यात्रा की तैयारी महीनों पहले आरंभ हो जाती है। यहाँ से लाखों कांवड़िए हरिद्वार की ओर प्रस्थान करते हैं।

कांवड़ यात्रा : चुनौतियाँ और समाधान

यह यात्रा आत्म–नियंत्रण, तपस्या और एकनिष्ठ भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। किंतु इसकी पवित्रता तब आहत होती है जब यात्रा में कुछ लोगों का आचरण हिंसक, अनुशासनहीन या सार्वजनिक शांति को भंग करने वाला हो जाता है।

इसलिए इस यात्रा में भव्यता के साथ कुछ चुनौतियाँ भी जुड़ी होती हैं, जैसे– भारी भीड़ प्रबंधन, कुछ स्थानों पर अनुशासनहीनता, ध्वनि प्रदूषण, सड़क जाम आदि। लेकिन प्रशासन के साथ स्वयंसेवी संगठनों, धार्मिक समितियों और आमजन की सहभागिता से इन चुनौतियों पर नियंत्रण पाया जा रहा है।

इन चुनौतियों का समाधान : संतुलित प्रशासन एवं जागरूक समाज

1. प्रशासनिक उपाय
    - **आगामी यात्रा के लिए पूर्व–अनुमति प्रक्रिया :** हर कांवड़ दल को यात्रा से पूर्व स्थानीय प्रशासन से पंजीकरण कराना अनिवार्य किया जाए।
    - **"नो–टॉलरेंस जोन" की घोषणा :** विशेष क्षेत्रों में उपद्रवी व्यवहार, ध्वनि प्रदूषण और वाहन स्टंट पर कड़ी निगरानी और तुरंत कार्रवाई।
    - **चलती कांवड़ यात्रा में सुरक्षा दलों की निगरानी :** पुलिस की "कांवड़ सुरक्षा टुकड़ी" जो केवल व्यवस्था, ट्रैफिक और शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करे।
    - **DJ एवं ध्वनि सीमा नियंत्रण :** धार्मिक भावना के अनुरूप मर्यादित ध्वनि तक सीमित अनुमति, साथ ही शांति क्षेत्र (अस्पताल, विद्यालय आदि) में पूर्ण प्रतिबंध।
2. सामाजिक जागरूकता एवं स्व–नियमन
    - **धार्मिक संगठनों और अखाड़ों की भूमिका :** कांवड़ संघों, अखाड़ों और स्थानीय धार्मिक संगठनों को अपने अनुयायियों के व्यवहार पर नैतिक मार्गदर्शन देना चाहिए।
    - **'श्रद्धा की मर्यादा' शपथ अभियान :** शिविरों में प्रारंभिक रूप से शपथ अभियान – "हम न तोड़ेंगे नियम, न दूसरों की शांति भंग करेंगे।"
    - **कांवड़ सेवा शिविरों द्वारा आचार–संहिता का वितरण :** यात्रा मार्गों पर सेवा शिविरों से भक्ति के साथ व्यावहारिक आचार–संहिता भी वितरित की जाए।
3. मीडिया एवं सोशल मीडिया प्रबंधन
    - असत्य या उत्तेजक वीडियो के प्रचार–प्रसार पर निगरानी।
    - सकारात्मक पहलुओं, सेवा कार्यों और अनुशासित कांवड़ियों की कहानियाँ अधिक दिखाना ताकि समाज में प्रेरणा बने।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यवस्थाएँ और उपाय :

इस विशाल जनसमूह को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारु रूप से यात्रा कराने हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस यात्रा को व्यवस्थित, सुरक्षित और भक्तिपूर्ण बनाने के लिए निम्न व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की हैं :

1. सुरक्षा व्यवस्था :
    - ड्रोन कैमरों और CCTV निगरानी के माध्यम से यात्रा मार्गों पर चौकसी।
    - PAC, पुलिस बल, ATS, RAF आदि की तैनाती।

- महिला सुरक्षा हेतु महिला पुलिस कर्मियों की विशेष टीमों की व्यवस्था।

2. **यातायात और मार्ग प्रबंधन :**
    - हाईवे व मुख्य सड़कों पर विशेष "कांवड़ पथ" बनाए जाते हैं ताकि यातायात और कांवड़ियों की आवाजाही में टकराव न हो।
    - भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध और वैकल्पिक मार्गों का निर्माण।

3. **स्वास्थ्य एवं सुविधा सेवाएँ :**
    - प्राथमिक चिकित्सा शिविर, एम्बुलेंस और मोबाइल अस्पतालों की तैनाती।
    - पेयजल, शौचालय, विश्राम स्थल एवं मोबाइल शौचालयों की व्यवस्था।

4. **प्रौद्योगिकी का उपयोग :**
    - यात्रा मार्गों की GPS आधारित निगरानी।
    - "कांवड़ एप" जैसी डिजिटल सेवाएँ जो यात्री को मार्ग, आपातकालीन सेवा व मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

5. **धार्मिक सौहार्द बनाए रखने हेतु सतर्कता :**
    - संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता।
    - सामाजिक मीडिया की मॉनिटरिंग ताकि अफवाहों व उकसावों पर तुरंत अंकुश लगाया जा सके।

आस्था की रक्षा हमारा दायित्व

कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक परम्परा नहीं, बल्कि राष्ट्र की आध्यात्मिक विरासत का जीवंत उदाहरण बन चुकी है। यह हमारी सामूहिक चेतना, धार्मिक एकता और संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक है। किंतु यह पवित्र परंपरा तभी स्थायी और सशक्त बनेगी जब भक्ति के साथ विवेक, श्रद्धा के साथ शांति और संकल्प के साथ संयम का पालन होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार, प्रशासन, समाजसेवी संस्थाएँ और श्रद्धालु—सभी मिलकर इस यात्रा को केवल शिवभक्ति की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक अनुशासन का उदाहरण बना सकते हैं

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धर्मनिरपेक्ष संवेदनशीलता के साथ व्यवस्थाओं का संचालन यह दर्शाता है कि राज्य और धर्म परस्पर सहयोग से श्रद्धा के मार्ग को सरल और सुरक्षित बना सकते हैं।

कांवड़ यात्रा भारत की धार्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सामूहिकता का सशक्त उदाहरण है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं ने इसे न केवल सुरक्षित बनाया है बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास को भी मजबूत किया है। आस्था और प्रशासन का यह समन्वय देशभर में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करता है।

कांवड़ यात्रा की आदर्श आचार—संहिता

सावन मास में होने वाली पवित्र कांवड़ यात्रा में सम्मिलित हर श्रद्धालु, सेवा दल, आयोजक और सामान्य

नागरिक के लिए निम्नलिखित आचार–संहिता का पालन न केवल धार्मिक अनुशासन का अंग है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा भी है ’

कांवड़ यात्रा की 10 प्रमुख मर्यादाएँ (आचार–संहिता)

1. **धार्मिक मर्यादा का पालन करें :**

   यात्रा शिवभक्ति का प्रतीक है, इसे किसी शक्ति प्रदर्शन या सार्वजनिक दंभ का माध्यम न बनाएं।

2. **शांति और अनुशासन बनाए रखें :**

   किसी से वाद–विवाद, झगड़ा या सामूहिक उन्माद की स्थिति से दूर रहें।

3. **ध्वनि मर्यादा का पालन करें :**

   DJ या लाउडस्पीकर का उपयोग यदि आवश्यक हो तो केवल मर्यादित स्तर पर हो। अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थल आदि के समीप विशेष ध्यान रखें।

4. **सड़क और यातायात नियमों का पालन करें :**

   आमजन को असुविधा पहुँचाना शिवभक्ति नहीं है। कांवड़ पथ के बाहर या यातायात बाधित करना वर्जित है।

5. **सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करें :**

   यात्रा मार्ग में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़, गंदगी से स्वयं भी बचें और दूसरों को भी रोकें।

6. **नशा और अनुचित व्यवहार से दूर रहें :**

   यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ, अश्लीलता या हिंसक आचरण का कोई स्थान नहीं है।

7. **स्त्री–सम्मान और सामाजिक संवेदनशीलता :**

   महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति शिष्टाचार और सौहार्द बनाए रखें।

8. **आपसी सहयोग और सेवा भाव रखें :**

   अन्य श्रद्धालुओं, राहगीरों और सेवा दलों के प्रति मित्रवत और सहयोगी बनें।

9. **प्रशासन के निर्देशों का पालन करें :**

   यात्रा मार्ग, समय, सुरक्षा निर्देश आदि को लेकर प्रशासन के दिशा–निर्देशों का आदरपूर्वक पालन करें।

10. **"भोले का भक्त – सच्चा नागरिक" बनें :**

    इस यात्रा से न केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें, बल्कि देश और समाज के लिए उत्तरदायी नागरिक के रूप में अपनी छवि भी बनाएं।

विशेष सुझाव :

धार्मिक पत्रिकाएँ इस आचार–संहिता को पोस्टर या स्टिकर फॉर्मेट में प्रकाशित कर सकती हैं, जिसे सेवा शिविरों, कांवड़ संघों और धार्मिक संस्थानों में प्रसारित किया जा सके। ◆

मो. : 9936411588

योगी सरकार भयमुक्त वातावरण बनाने में सफल

–सुधा मिश्रा

योगी आदित्यनाथ ने आठ वर्ष पूर्व जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो अपराधियों और अपराध पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाना उनके लिए सर्वोपरि था। अपराधियों की वजह से सर्वत्र असुरक्षा का बोध यहाँ नागरिकों में व्याप्त हो गया था। योगी जी के सत्ता में आने के पश्चात् अपराधियों के खिलाफ लगातार सघन अभियान चला कर प्रदेश की छवि को सकारात्मक करना और आम जन में सुरक्षा का बोध कराने का कार्य लगातार चल रहा है। यह ऐसा विषय समय के साथ–साथ साबित हुआ है कि आज पूरे प्रदेश में न केवल सुरक्षा का बोध है बल्कि अपराधियों का खात्मा तेजी से हो रहा है। अपराधियों के खिलाफ योगी मॉडल आज सम्पूर्ण भारतवर्ष में अपनी अमिट पहचान बना चुका है। कई राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। पर इस परिणाम के पीछे लगातार कठिन कार्य, नियन्त्रण, नीति और मार्गदर्शन शामिल है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर नियमित अपडेट लेकर त्वरित कार्रवाई हेतु मार्गदर्शन देते रहते हैं। जिलेवार अपराधियों की लिस्ट बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। योगी सरकार द्वारा किया गया कार्य अभूतपूर्व है। कुछ खास किस्म के अपराधी जिनके खिलाफ कार्यवाही की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था, वजह उन अपराधियों की राजनीतिक दखल बेहद मजबूत थी उनके खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई करके अपने वायदे को ”अपराधियों को पाताल लोक से भी खोज कर सजा देने” की प्रतिबद्धता को दोहराया है। आज पूरे प्रदेश में न केवल सभी में सुरक्षा का बोध है, बल्कि योगी सरकार में सबका अमिट विश्वास भी है। आज अपराधी प्रदेश छोड़ कर भाग रहे हैं। वास्तव में जनता की आवश्यकता और उस पर कार्य सीएम योगी न केवल बेहतर ढंग से समझते हैं बल्कि जमीनी कार्यवाही भी नीतिगत रूप से करते हैं।

योगी सरकार की प्रतिबद्धता और उपलब्धि की पुष्टि आंकड़ें भी कर रहे हैं। योगी सरकार की पुलिस ने विगत आठ वर्षों में दुर्दांत अपराधियों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। मेरठ जोन अपराधियों का हब बन गया था सबसे अधिक 77 अपराधी मेरठ जोन में ढेर किये गए। उसके पश्चात् देखा जाए तो एनकाउंटर की कार्यवाही में दूसरे

उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जब यह कहा था कि "अपराधी या तो जेल में होगा या प्रदेश से बाहर" तब बहुत सारे लोगों को इस वाक्य की समझ वास्तविक रूप से नहीं हो रही थी पर विगत आठ वर्षों में लगातार किये गए कार्यों और पुलिसिया एक्शन की वजह से अपराधी प्रदेश छोड़ने पर मजबूर हुए हैं और जिन्होंने प्रदेश नहीं छोड़ा, उन्हें समाप्त कर हमेशा के लिए दिया गया है।

नंबर पर वाराणसी जोन और तीसरे नंबर पर आगरा जोन है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि ये समस्त अपराधी ऐसे थे जिनका डर आम जन में व्यापक रूप से था। इस दौरान पुलिस ने कुल 14,741 मुठभेड़ की कार्यवाही की जिनमें 30,293 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में 9202 अपराधी घायल हुए। इन आंकड़ों के पीछे पुलिस विभाग की शहादत भी छिपी है अपराधियों से लोहा लेते हुए 18 पुलिस कर्मी शहीद हुए जबकि 1700 पुलिस कर्मी घायल भी हुए है। डीजीपी राजीव कृष्णा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुठभेड़ मेरठ जोन में हुए है जहां पुलिस ने 4,183 कार्यवाही की और इनमें 7,871 अपराधियों को पकड़ा गया, 2,839 अपराधी घायल हुए और 77 कुख्यात अपराधियों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है। एक तरफ मेरठ जोन की मुठभेड़ के दौरान जहाँ 2,839 अपराधी घायल हुए वही 452 पुलिसकर्मी भी घायल हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दो पुलिसकर्मी शहीद भी हुए। वाराणसी जोन में 1,041 मुठभेड़ हुई, जिनमें 2,009 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अपराधियों को मुठभेड़ में हमेशा मारा गया। एक तरफ इस मुठभेड़ में 605 अपराधी घायल हुए तो वही 96 पुलिसकर्मी भी इनसे लोहा लेते हुए घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी जोन एनकाउंटर कार्रवाई में दूसरे स्थान पर रहा है आगरा जोन तीसरे स्थान पर रहा है। आगरा में 2,288 एनकाउंटर की कार्रवाई की गई, जिनमें 5,496 अपराधियों को पकड़ा गया। इस मुठभेड़ में 715 अपराधी घायल हुए, 19 अपराधी मार गिराए गए। इस कार्रवाई में 56 पुलिसकर्मी भी घायल हुए है।

कमिश्नरेट में सबसे अधिक लखनऊ कमिश्नरी में 11 अपराधियों को ढेर किया गया। एनकाउंटर के आंकड़ें यह बयाँ कर रहे है कि लखनऊ जोन में 790 मुठभेड़ के दौरान 15 दुर्दांत अपराधियों को हमेशा के लिए नीद के आगोश में सुला दिया गया। **प्रयागराज जोन में 506 मुठभेड़ के दौरान** 10 अपराधियों को हमेशा के लिए नींद के आगोश में सुला दिया गया, बरेली जोन में 1,962 मुठभेड़ों में 15, कानपुर जोन में 657 मुठभेड़ों में 11 और गोरखपुर जोन में 594 मुठभेड़ों में 8 अपराधियों को मार दिया गया। लखनऊ कमिश्नरी में 126 मुठभेड़ों में 11, गौतमबुद्ध नगर में 1,035

मुठभेड़ में 9, कानपुर कमिश्नरी में 221 मुठभेड़ में 4, वाराणसी कमिश्नरी में 118 मुठभेड़ में 7, आगरा कमिश्नरी में 426 मुठभेड़ में 7 और प्रयागराज कमिश्नरी में 126 मुठभेड़ में 5 अपराधियों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। यह आंकड़ें सफलता की कहानी बयाँ कर रहे हैं। नेतृत्वकर्ता यदि उद्देश्य को लेकर तत्पर हो तो पूरी टीम उसे हासिल करने को लेकर कार्य करती है। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का सबसे बड़ा लाभ प्रदेश के नागरिकों को हो रहा है। अब बाहर से निवेशक भी यहाँ तेजी से निवेश करना शुरू कर चुके है, इससे प्रदेश को बड़ा लाभ भी होगा।

उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जब यह कहा था कि "अपराधी या तो जेल में होगा या प्रदेश से बाहर" तब बहुत सारे लोगों को इस वाक्य की समझ वास्तविक रूप से नहीं हो रही थी पर विगत आठ वर्षों में लगातार किये गए कार्यों और पुलिसिया एक्शन की वजह से अपराधी प्रदेश छोड़ने पर मजबूर हुए हैं और जिन्होंने प्रदेश नहीं छोड़ा उन्हें सदा–सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया गया है। आज उत्तर प्रदेश के कानून–व्यवस्था की न केवल चारों तरफ सराहना हो रही है, बल्कि यह विषय राष्ट्रीय चर्चा का विषय भी बना हुआ है। आम जनता अब सुकून और निश्चिन्त्ता के साथ अपना जीवन उत्साह के साथ बिना किसी डर के व्यतीत कर रही हैं उसकी कल्पना को साकार योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता और उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रतिबद्धता ने पूरा किया है। योगी सरकार की नीति के तहत संगठित अपराध, माफियागीरी और अवैध वसूली पर कड़ा प्रहार करते हुए पुलिस द्वारा इसमें व्यापक कमी लाई गई है। अपराधियों की संपत्ति कुर्की, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही और एनएसए जैसे कानूनों के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू कर सभी अपराधियों को स्पष्ट मैसेज दे दिया गया है कि अब उत्तर प्रदेश में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। योगी सरकार प्रदेश की उन चुनिन्दा सरकारों में शामिल है, जिन्होंने अपराधियों के खिलाफ जो आंकड़ें प्रदर्शित किये हैं उसका प्रभाव जमीनी स्तर पर भी चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। त्वरित, कठोर और साहसिक कार्रवाई ने अपराधियों को उत्तर प्रदेश छोड़ने पर मजबूर किया है, परिणाम स्वरुप उत्तर प्रदेश अब भयमुक्त और सुरक्षित राज्य के रूप में अपनी अलग सशक्त पहचान बना चुका है। विस्तृत विवरण और जमीनी सच्चाई के आधार पर यह कहा जा सकता है कि योगी सरकार भयमुक्त वातावरण बनाने में सफल रही है। ◆

मो. :8090005531

औद्योगिक विस्तार के आठ साल

–प्रज्ञा पांडेय

उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार के आठ साल पूर्ण हो गए। उत्तर प्रदेश के लिए विगत 8 साल बेहद परिवर्तनकारी रहे हैं। कानून–व्यवस्था में सुधार तो हुआ ही है, राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास,औद्योगिक निवेश में भी बूम नजर आया है। महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भी प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2017 से सरकार ने राज्य की छवि बदलने की दिशा में सार्थक भूमिका निभाई है। सरकार ने उसने विधि व्यवस्था को सुधारने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और विकास परियोजनाओं को गति देने पर विशेष जोर दिया है। इसमें किसी भी तरह की कोताही से बचने के लिए हर स्तर पर अनुश्रवण और सतत निगरानी का सिलसिला सरकार द्वारा बदस्तूर जारी रखा गया है।

सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर जो सख्त कार्रवाई की है, उसका असर प्रदेश के औद्योगिक विकास पर साफ नजर आ रहा है। संगठित अपराध को रोकने के लिए जहां पुलिस और प्रशासन को मजबूती दी गई, वहीं मुठभेड़ नीति के तहत कई अपराधी गिरफ्तार भी किए गए और कुछ मुठभेड़ में मारे भी गए। महिला सुरक्षा के लिए एंटी–रोमियो स्क्वॉड का गठन किया। यह कदम महिलाओं और युवतियों को छेड़छाड़ और अन्य अपराधों से सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया। प्रदेश में कानून–व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए न केवल थानों में आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई गईं, बल्कि तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों का व्यापक स्तर पर उपयोग भी सुनिश्चित किया गया। राज्य में अनेक एक्सप्रेस–वे, हवाई अड्डे, और रेलवे परियोजनाओं के जरिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जहां उत्तर प्रदेश के विकास को विस्तार प्रदान किया, वहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश को समृद्धि के शिखर पर ले जाने की कोशिश भी की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस–वे से व्यापार और परिवहन जहां आसान होगा, वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र को औद्योगिक हब बनाने की सरकार की योजना को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे संबल प्रदान करेगा।

लखनऊ, कानपुर, आगरा और गाजियाबाद में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार यह बताने के लिए काफी है कि सरकार प्रदेश में निवेश की किसी भी संभावना को अपने हाथ से जाने देने के पक्ष में नहीं है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के अनेक प्रयास वह पहले भी कर चुकी है

TO
GANGA EXPRESSWAY PROJECT,
GROUP-II
SHAHJAHANPUR, U
HGIEL

और उसके बेहतर नतीजे भी सामने आए हैं। इन्वेस्टर्स समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जैसे कार्यक्रमों के जरिए योगी सरकार ने देश–विदेश के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। एक जिला–एक उत्पाद योजना को क्रियान्वित किया। इसका परिणाम यह रहा कि हर जिले की विशिष्ट हस्तकला और उद्योग को गति मिली। इससे स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यापारियों को भी रोजगार के अनेक अवसर मिले। राज्य में आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और डाटा सेंटर हब विकसित किए जा रहे हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने मिशन शक्ति अभियान शुरू किया,इसकी जितनी भी सराहना की जाए, कम है। उत्तर प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ा कर महिलाओं से जुड़े मामलों का त्वरित गति से समाधान करने का जो प्रयोग हो रहा है, उससे राज्य की महिलाएं राहत महसूस कर रही हैं। महिला स्वयं सहायता समूह गठित कर महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का सरकार का प्रयास बेहद प्रभावी रहा है। सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प लागू किया गया। स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई गईं। अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग देकर सरकार ने युवाओं के हौसलों को नई उड़ान दी है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने कई अहम कदम उठाए, जिनमें नए विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों की स्थापना शामिल है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से की गई और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया।

यही नहीं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और उन्हें सुविधाएं देने के लिहाज से योगी सरकार ने प्रदेश के 11 जिलों में एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का निर्णय लिया है। इसमें संदेह नहीं कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की राज्य की उद्यमिता में बड़ी भूमिका है। इसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता। कदाचित् इसीलिए योगी सरकार ने एमएसएमई एस्टेट्स की स्थापना का विचार किया है। राज्य के 11 जिलों में 15 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू होना इस बात का द्योतक है कि सरकार बड़े उद्योगों को लेकर जितनी गंभीर है, उतनी ही सजग वह राज्य के लघु उद्योगों को लेकर भी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने जो रूपरेखा बनाई है, उसके मुताबिक यूपी के विभिन्न जिलों में फैले इन औद्योगिक क्षेत्रों को कुल 764.31 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। यहां 872 भूखंड निवेशकों को अपना उद्योग लगाने के लिए दिए जाएंगे। अलीगढ़, प्रतापगढ़, मऊ समेत 11 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का निर्णय प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अलीगढ़ के गभाना में 116 एकड़, एटा के जलेसर में 6.8 एकड़, फिरोजाबाद के टूंडला में 19 एकड़, सिरसागंज में 10 एकड़, कानपुर देहात के अकबरपुर (कुंभी) में 59 एकड़ तथा दुवारी में 172 एकड़, ललितपुर के बीघाखेत में 9.8 एकड़, पुलवारा में 44 एकड़, झरर में 8.6 एकड़ तथा महोबा में 37 एकड़ क्षेत्र के भूखंड एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार, प्रयागराज के सदर में 8 एकड़, प्रतापगढ़ के रानीगंज में 39.7 एकड़, मिरजापुर के चुनार में 35 एकड़, मऊ के सदर में 84 एकड़ तथा रायबरेली सदर में 58 एकड़ क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी एमएसएमई सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना पर काम कर रहा है। प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र में एमएसएमई इकाइयों की स्थापना के लिए 500 एकड़ क्षेत्र आरक्षित किया है। यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अतिशीघ्र गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा स्थित सेक्टर 28 में 125 करोड़ की लागत से फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाना है। इसके मास्टर प्लान और अन्य रिपोर्ट् तैयार करने की दिशा में काम चल रहा है। यह बहुमंजिला फ्लैटेड फैक्ट्री लगभग 38,665 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में बननी है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बड़ी मदद मिलेगी।

योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जिस तरह रोजगार सृजन और गरीबी निवारण के लिए व्यापक निवेश आकर्षित

करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है औद्योगिक प्रगति की दिशा में प्रयास कर रही है, वह अपने आप में बड़ी पहल है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हाल के वर्षों में एमएसएमई सेक्टर में हुई प्रगति ने राज्य में रोजगार के अधिकाधिक अवसर मुहैया कराए हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम प्रदेश एवं देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि एमएसएमई स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने में अहम योगदान दे रहे हैं। देश से वस्तुओं के कुल निर्यात में एमएसएमई खंड की हिस्सेदारी 45 फीसदी से अधिक है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इनका योगदान लगभग 30 फीसदी है। देश में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सेमीकंडक्टर जैसे मूल्यवान क्षेत्रों सहित बड़े औद्योगिक संकुलों को जिस तरह महत्व दिया जा रहा है, उतना ही ध्यान एमएसएमई के विकास के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करने पर देने की जरूरत है और इस बात को उत्तर प्रदेश सरकार बखूबी जानती और समझती है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सुनियोजित रूप से कदम बढ़ाता प्रतीत हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई की संख्या देश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले विशेष रूप से एमएसएमई के लिए 11 जिलों में 15 औद्योगिक क्षेत्र तैयार करने से जुड़ी घोषणाएं हुई हैं। इनमें यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी शामिल है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के ये प्रयास सही दिशा में हैं। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 60 फीसदी है और उत्तर प्रदेश के निर्यात में भी इसकी हिस्सेदारी 46 फीसदी तक पहुंच जाती है। राज्य की ऐसी इकाइयों की हिस्सेदारी देश के कुल एमएसएमई में लगभग 14 फीसदी है। एक जिला एक उत्पाद जैसी विशेष योजनाएं परंपरागत एवं कारीगरी कौशल को नये सिरे से बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही हैं। देश में सर्वाधिक जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश स्थानीय उत्पादों के दम पर एक नया एवं विशिष्ट बाजार तैयार करने में सफल हो रहा है। वर्ष 2023–24 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 13 फीसदी रही जो प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (एसजीडीपी) दर 7.5 फीसदी से आगे निकल गई। वर्तमान मूल्यों पर विनिर्माण राज्य की अर्थव्यवस्था में 27 फीसदी योगदान दे रहा है। गौर करने की बात यह है कि राज्य के लगभग सभी जिलों में निवेश बढ़ रहा है। यह प्रगति एमएसएमई क्षेत्र को आगे बढ़ने में मदद करती है, साथ ही एक संतुलित औद्योगिक तंत्र विकसित करने में भी सहायता मिली है। ये सभी प्रयास उपयुक्त दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं किंतु अब भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य में मौजूद कुल एमएसएमई में महिलाओं द्वारा संचालित एमएसएमई की हिस्सेदारी मात्र 33 फीसदी है। यह अनुपात कई राज्यों की तुलना में कम है। लक्षित कौशल विकास, वित्त की उपलब्धता, महिला केंद्रित औद्योगिक संकुल रोजगार एवं उत्पादन को और बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था चुनौती और अवसर दोनों पेश कर रही है। कृषि–प्रसंस्करण, खाद्य संरक्षण, ग्रामीण हस्त–शिल्प और कृषि उपकरण विनिर्माण खंडों में अपार संभावनाएं हैं जिनका पर्याप्त लाभ उठाने की जरूरत है। अगर सरकार इस दिशा में सुनियोजित ढंग से काम करे, तो प्रदेश के विकास में उसकी उपलब्धियों का ग्राफ न केवल विस्मयकारी होगा बल्कि इससे दूसरे राज्यों को भी कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। ◆

मो. : 7459998968

विश्व युवा कौशल दिवस
विश्व युवा कौशल दिवस-2025
विश्व युवा कौशल दिवस-2025

प्रदेश के कौशल का महाकुम्भ

–प्रदीप कुमार गुप्ता

उत्तर प्रदेश भारत की हृदयस्थली के रूप में जगविख्यात है। यहां की गंगा–यमुना जैसी पावन नदियों के किनारे सदियों से सभ्यता और संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती चली आ रही है। इन्हीं के चंचल, गम्भीर, शीतल, शान्त और निर्मल जल से सिंचित हमारे देश को गंगा–जमुनी तहजीब का देश भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश न केवल देश की सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है, बल्कि जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अक्सर कहते हैं कि प्रकृति व परमात्मा की सर्वाधिक कृपा भी इसी प्रदेश पर बरसती है। इसी का साकार उदाहरण राज्य के हस्तशिल्पी, कारीगर तथा उनके कौशल से विकसित हमारे परम्परागत शिल्प उत्पाद हैं। प्रदेश के सभी 75 जनपदों की अलग–अलग विशेषताएं हैं। इसी के अनुरूप यहां पर अलग–अलग शिल्पों का विकास हुआ है। इन कारीगरों, हस्तशिल्पियों एवं विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों के हुनर को उड़ान देने और उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत से देश–दुनिया के लोगों को परिचित कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश इण्टरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से अभिनव मंच उपलब्ध कराया है।

परम्परागत उद्यमों के विकास के साथ ही, राज्य सरकार ने विकास के अन्य सभी क्षेत्रों में अच्छे कार्य किए हैं, राज्य की कानून–व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिली है। इन कार्यों से राज्य के बदले परसेप्शन से उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है। प्रदेश के विकास को गति तथा दिशा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा जो प्रयास विगत 08 वर्षों में किए गए हैं, उनके परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। प्रदेश में हुए विकास का लाभ यहां के उद्यमी, कारीगर, हस्तशिल्पी सहित अन्य क्षेत्रों के लोग उठा सकें, इन्हें देश और दुनिया तक अपने उत्पादों, नवाचारों और सेवाओं को पहुंचाने का माध्यम मिल सके, इस दृष्टि से, प्रदेश में हुए विकास के दृष्टिगत 21 से 25 सितम्बर, 2023 तक ग्रेटर नोएडा के इण्डिया एक्सपो सेण्टर एवं मार्ट में 'यू.पी. इण्टरनेशनल ट्रेड शो' के प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी ने किया।

वर्ष 2023 में आयोजित यू.पी. इण्टरनेशनल ट्रेड शो के प्रथम संस्करण में 66 देश के 400 से अधिक बायर्स ने

प्रतिभाग किया। ट्रेड शो में प्रदेश के 2,000 से अधिक निर्माताओं एवं एक्जीबिटर्स ने अपने–अपने उत्पाद प्रदर्शित किए, जिनमें स्थापित औद्योगिक घरानों से लेकर नए उद्यमियों तक के विभिन्न श्रेणियों के उत्पाद शामिल थे। प्रथम संस्करण में उत्तर प्रदेश के 54 जी.आई. उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इनके 108 एक्जीबिटर्स ने ट्रेड शो में उपस्थित होकर अपनी कुशलता व कौशल का परिचय दिया। यह ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को दर्शाने वाला माध्यम बन गया है। रक्षा, कृषि, उद्योग, ई–कॉमर्स, शिक्षा, अवस्थापना, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स, हैण्डलूम, टेक्सटाइल के उत्पादों सहित विभिन्न अन्य सेक्टरों की प्रदर्शनियां यू.पी. इण्टरनेशनल ट्रेड शो के प्रथम संस्करण का हिस्सा बनीं। ट्रेड शो के माध्यम से प्रदेश की महिला उद्यमियों एवं युवा उद्यमियों तथा उभरते निर्यातकों को देश–विदेश के क्रेताओं से विचारों व तकनीक के आदान–प्रदान तथा व्यावसायिक साझेदारी करने का अवसर प्राप्त हुआ।

वर्ष 2024 में उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ द्वारा 25 सितम्बर को यू.पी. इण्टरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन किया गया। इसने प्रदेश के कारीगरों, शिल्पकारों, उद्यमियों व दुनिया भर के बायर्स को एक मंच पर लाकर उत्तर प्रदेश की असीम सम्भावनाओं की भूमि पर सभी सम्बन्धित पक्षों को अवसर उपलब्ध कराया। यू.पी. इण्टरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में दक्षिण एशिया में प्रभावशाली जी.डी.पी. वाला देश वियतनाम भी भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ। इससे यह आयोजन अपनी वैश्विक पहचान की ओर बढ़ चला है। उपराष्ट्रपति जी ने इस आयोजन को 'अवसरों की टोकरी' कहा। निःसंदेह यह टोकरी प्रधानमंत्री जी के 'आत्मनिर्भर व विकसित भारत' तथा 'स्थानीय से वैश्विक' के मंत्र को साकार करने वाले हमारे हुनरमन्द हाथों के उत्पाद रूपी विविध फलों–फूलों से भरी है।

यू.पी. इण्टरनेशनल ट्रेड शो–2024 में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के उद्यमियों के उत्पादों को भी प्रस्तुत किया गया। इसमें जी–2–जी, जी–2–बी तथा अन्य अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए। जिसके माध्यम से प्रदेश की सामर्थ्य तथा यहां की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के विभिन्न पक्षों से दुनिया के उद्यमियों का साक्षात्कार हुआ। ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में 2,500 से अधिक एक्जीबिटर्स तथा 350 से अधिक फॉरेन बायर्स उपस्थित हुए। ट्रेड शो में विभिन्न सेक्टरों से सम्बन्धित स्टॉल लगाए गए। यू0पी0 इण्टरनेशनल ट्रेड शो में खादी के परिधानों का फैशन शो और कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया। इस शो से छोटे–छोटे उद्यमियों को भी ग्लोबल शोकेस मिला है।

मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश के निर्माता एवं उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने और असीमित अवसरों को साकार करने के एक मंच के रूप में यू.पी. इण्टरनेशनल ट्रेड शो सामने आया है। यह शो विभिन्न सेक्टरों के प्रदेश के उत्कृष्ट उत्पादों तथा इनोवेशन आदि को विश्वपटल पर शोकेस करने का केन्द्र बन गया है। मुख्यमंत्री जी ने यू.पी. इण्टरनेशनल ट्रेड शो को 'प्रदेश के उद्यमियों का महाकुम्भ' कहा है। इस महाकुम्भ में प्रदेश के सभी जनपदों के उद्यमी, कारीगर, हस्तशिल्पियों के हुनर को एक साथ देखने, समझने और उनसे जुड़ने का अवसर देश–दुनिया के क्रेताओं और उद्यमियों को मिलना सम्भव हुआ है। यू.पी. इण्टरनेशनल ट्रेड शो प्रदेश की औद्योगिक प्रगति, सांस्कृतिक विरासत एवं सामाजिक विविधता के अद्भुत संगम से दुनिया को परिचित करा रहा है।

27 जून, 2025 को मुख्यमंत्री जी ने अन्तरराष्ट्रीय एम.एस.एम.ई. दिवस के अवसर पर यू.पी. इण्टरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण का कर्टेन रेजर जारी किया है। इनोवेट, इन्टीग्रेट, इन्टरनेशनलाइज के मंत्र के साथ ट्रेड शो के तृतीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितम्बर 2025 तक ग्रेटर नोएडा के इण्डिया एक्सपो सेण्टर एवं मार्ट किया जाएगा। यू.पी. इण्टरनेशनल ट्रेड शो का तृतीय संस्करण भी अपने पूर्ववर्ती दोनों संस्करणों की भांति सफल हो, इसके लिए इसकी तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू हो गयी हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 77 उत्पादों को जी.आई. टैग मिल चुका है। इन उत्पादों की प्रदर्शनियां भी यू.पी. इण्टरनेशनल ट्रेड शो–2025 में लगायी जाएंगी। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 75 नए उत्पादों को जी.आई. टैग दिलाए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यह अपने हस्तशिल्पियों, कारीगरों

एवं एम.एस.एम.ई. उद्यमियों के प्रति प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है। ट्रेड शो में हैण्डलूम एण्ड हैण्डीक्राफ्ट, एम.एस.एम.ई., जी.आई. टैग प्रोडक्ट्स, ओ.डी.ओ.पी. तथा बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस से सम्बन्धित प्रदर्शनियां और कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। यहां उद्यमी अपने उत्पाद की बिक्री भी कर सकेंगे।

यदि प्रदेश के परम्परागत हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत की बात करें, तो राजधानी लखनऊ अपनी चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है और पीलीभीत अपनी बांसुरी के लिए। मुरादाबाद का पीतल उद्योग बहुत पहले से ही अपनी चमक बिखेर रहा है, फिरोजाबाद का कांच उद्योग भी पूरे देश में विशिष्ट पहचान रखता है। इसी तरह सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, अमरोहा के वाद्य यन्त्र, वाराणसी की सिल्क की साड़ियां सहित हर जनपद के कोई न कोई विशिष्ट उत्पाद और उनसे जुड़े कारीगर, हस्तशिल्पी एवं उद्यमी अपनी प्रतिभा से न केवल रोजगार अर्जित करते हुए अपने परिवार का पालन–पोषण कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश की परम्परागत विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। बीच का एक कालखण्ड ऐसा भी आया, जब हमारे प्रदेश के इस विश्व प्रसिद्ध हुनर को उपेक्षा और उदासीनता का दंश झेलना पड़ा। तेजी से आधुनिक होते विश्व में तकनीकी और नवाचार में प्रदेश के हस्तशिल्पी–कारीगर पीछे रह गए। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की रीढ़ हमारे कुशल कारीगर विकास की दौड़ में कहीं खो से गए। एक समय ऐसा भी था जब उत्तर प्रदेश की हमारी विरासत के प्रतीक यह हस्तशिल्पी पलायन कर रहे थे और पहचान के संकट से जूझ रहे थे। ऐसे में प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को गहरी चोट पहुंची।

वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की बागडोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में आयी, जिससे प्रदेश के कायाकल्प का एक भगीरथ प्रयत्न और नया युग शुरू हुआ। ऐसे में प्रदेश के परम्परागत हस्तशिल्पों को संजीवनी तब मिली, जब वर्ष 2018 में एक अभिनव योजना के रूप में 'एक जनपद–एक उत्पाद' योजना की शुरुआत हुई। यह योजना प्रदेश के सदियों पुराने उद्यमों, सूक्ष्म निर्माण कारीगरों के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है। इसके तहत प्रदेश के सभी 75 जनपदों के यूनिक प्रोडक्ट्स को तकनीक, मार्केट, पैकेजिंग तथा डिजाइन से जोड़ा गया। इन उत्पादों के एक्सपोर्ट की दिशा में भी कार्य प्रारम्भ हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा मुख्यमंत्री जी अपने यहां आने वाले विशिष्ट मेहमानों को ओ.डी.ओ.पी. के उपहार भेंट करते हैं। इससे इनसे जुड़े लोगों और उत्पादों को वैश्विक पहचान मिली है। इससे हमारे कारीगरों और हस्तशिल्पियों का हुनर पूरी दुनिया में पहुंच रहा है और उन्हें सम्मान भी मिल रहा है।

इसी के साथ ही, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना, एम.एस.एम.ई. इकाइयों को स्टाम्प शुल्क में छूट, पूंजीगत उपादान, तकनीकी उन्नयन, ऊर्जा दक्षता आदि हेतु सहायता दिए जाने, एम.एस.एम.ई. नीति–2022 आदि जैसे उठाए गए कदमों से प्रदेश के परम्परागत कारीगरों और हस्तशिल्पियों की कार्य कुशलता में वृद्धि हुई है। लगभग 96 लाख एम.एस.एम.ई. इकाइयों वाला उत्तर प्रदेश, देश में सबसे अधिक एम.एस.एम.ई. वाला प्रदेश भी है। इन इकाइयों में से 97 प्रतिशत से अधिक इकाइयां सूक्ष्म क्षेत्र की हैं, जिनका टर्नओवर 05 करोड़ रुपये से कम है। यह क्षेत्र कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। इस रूप में यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। वर्ष 2017 से पूर्व, जो प्रदेश 80 से 85 हजार करोड़ रुपये का

एक्सपोर्ट करता था, वर्तमान में, वही उत्तर प्रदेश 02 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात कर रहा है। इसमें विगत 08 वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान तथा ओ.डी.ओ.पी. योजना को देश भर में सराहा गया है। इसी तर्ज पर सितम्बर, 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'पीएम विश्वकर्मा' नाम से एक नई योजना पूरे देश में प्रारम्भ की है। विगत 08 वर्षों में प्रदेश में अन्य अनेक योजनाएं भी संचालित की गई हैं। निजी क्षेत्र में औद्योगिक निवेश पार्क बनाने के लिए प्लेज पार्क योजना लाई गई है, जिसके तहत उद्यम लगाने के लिए कनेक्टिविटी सहित अन्य व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जा रही हैं। हॉरिजेन्टल के स्थान पर वर्टिकल रूप में फ्लेटेड फैक्ट्री का कार्य प्रारम्भ किया गया है, इससे अनेक उद्यमों की एक साथ स्थापना की जा सकेगी। बहुत ज्यादा भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रदेश के युवाओं को उद्यमों की स्थापना से जुड़ी सभी जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए लखनऊ के किसान बाजार में 'यूथ अड्डा' बनाया गया है। यह 'यूथ अड्डा' उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन व नेतृत्व में प्रदेश में लागू 25 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज ने विभिन्न सेक्टरों के उद्यमियों को अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रदेश में नवाचार की नई संस्कृति विकसित की गई है। 24 जनवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर प्रदेश में प्रारम्भ की गई अभिनव पहल मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 'सीएम युवा' की चर्चा किया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। 'सीएम युवा' 10 लाख युवाओं को उद्यमी बनाए जाने के लक्ष्य से प्रारम्भ यह योजना अब तक 55,000 से ज्यादा युवाओं को लाभान्वित कर चुकी है। इसके अन्तर्गत युवाओं को 05 लाख रुपये का गारण्टी और ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे युवा अपने नवाचार को साकार रूप प्रदान कर विश्वपटल पर छाने की दिशा में अग्रसर हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेक कार्य प्रारम्भ किए हैं। विकसित भारत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। विकसित और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला हमारी परम्परागत विरासत का प्रतीक एम.एस.एम.ई. के हमारे उद्यम हैं। हमारा राज्य भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर विकसित राज्यों की श्रेणी में आ चुका है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में एम.एस.एम.ई. सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। देश को 05 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाए जाने के लक्ष्य के सापेक्ष उत्तर प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में सभी कार्य संचालित किए जा रहे हैं। राज्य आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन का केन्द्र बन चुका है। विगत 08 वर्षों में उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एक्सप्रेसवेज का व्यापक नेटवर्क बना है। एक्सप्रेसवेज के किनारे नए–नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इन कार्यों से प्रदेश सभी के आकर्षण का केन्द्र बना है। इसके दृष्टिगत यू.पी. इण्टरनेशनल ट्रेड–शो का महत्व और भी बढ़ जाता है। विगत दो संस्करणों की भांति यू.पी. इण्टरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा संस्करण भी उत्तर प्रदेश की विरासत के साथ विकास की संकल्पना को विश्व के सामने रखने में सफल होगा। आइए, आप भी यू.पी. इण्टरनेशनल ट्रेड शो का हिस्सा बनिए। ◆

विश्व युवा कौशल दिवस-2025

मो. : 7705800992

भारत के विकास में गोरखपुर का योगदान सराहनीय : राष्ट्रपति

—यशोदा श्रीवास्तव

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा शायद ही कोई मुख्यमंत्री हो, जिसे अपने शहर में चार बार महामहिम राष्ट्रपतियों के स्वागत का अवसर मिला हो। तीस जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गोरखपुर आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कर कमलों से चौथी बार राष्ट्रपति का स्वागत किया। महामहिम द्रौपदी मुर्मू गोरखपुर आने वाली छठीं राष्ट्रपति हैं। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद अपने कार्यकाल में तीन बार गोरखपुर आ चुके हैं और तीनों ही बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ की पावन धरती पर उनका स्वागत किया।

महामहिम द्रौपदी मुर्मू के पहले यहां पांच राष्ट्रपति गोरखपुर आ चुके हैं इसमें देश के प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम भी शामिल है। इसके बाद आने वाले राष्ट्रपतियों में सर्वपल्ली डाक्टर राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और अब छठवीं राष्ट्र पति के रूप में द्रोपदी मुर्मू का आगमन हुआ है। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रेवती रमण पांडेय के आमंत्रण पर गोरखपुर आए थे उन्होंने विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में ''विजन 2020'' पर छात्र और शिक्षकों से संवाद किया था।

कार्यकाल समाप्ति के बाद फरवरी 2011 में डॉ. कलाम एक बार फिर गोरखपुर आए। तब गोरखनाथ क्षेत्र स्थित सेंट जोसेफ हाई स्कूल में गोरखपुर–बस्ती मंडल के छात्र–छात्राओं से उन्होंने 'विज्ञान और प्रकृति' के संरक्षण विषय पर संवाद किया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मार्च 2009 में वायुसेना केंद्र गोरखपुर में 105 हेलिकॉप्टर यूनिट और 108 स्क्वॉड्रन को 'प्रेसिडेंशियल स्टैण्डर्स सम्मान देने आईं थीं।

बतौर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहली बार 10 दिसंबर, 2018 को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के

संस्थापक सप्ताह समारोह, दूसरी बार 28 अगस्त, 2021 को आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के उद्‌घाटन और तीसरी बार चार जून 2022 को गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के शुभारंभ अवसर पर गोरखपुर आए थे।

राष्ट्रपति महामहिम द्रोपदी मुर्मू संभवतः पहली राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सर्वाधिक तीस घंटे गोरखपुर में बिताए।

तीस जून को राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू दोपहर 12.30 पर गोरखपुर पहुंचीं। साथ में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। गोरखपुर हवाई अड्डे पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। क्षेत्रीय सांसद राव किशन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी महामहिम राष्ट्रपति का स्वागत अभिनन्दन किया। यहां गोरखपुर नगर निगम के मेयर डाक्टर मंगलेश श्रीवासन ने राष्ट्रपति को चांदी की चाबी भेंट कर उनका स्वागत किया। कहा कि यह गोरखपुर के विकास की चाबी है। यहां हुए चप्पे—चप्पे के विकास का अनावरण कर आप जनता को समर्पित करें। चाबी हाथ में लेते हुए राष्ट्रपति महोदया मुस्कुरा उठीं।

तीस जून को सायंकाल उन्होंने एम्स में आयोजित दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। यहां 61 डाक्टरों को उन्होंने अपने हाथों मेडल व प्रमाण पत्र दिया। कहा कि डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं। लोगों की इस धारणा को बचाए रखना आपकी जिम्मेदारी है।

राष्ट्रपति महोदया के रात्रि विश्राम का स्थल सर्किट हाउस था। उन्होंने रात का प्रसाद गोरखनाथ मंदिर में किया जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल महोदया भी मौजूद थीं। इसके पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की।गोरखपुर में संपन्न राष्ट्रपति महोदया के सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदया साथ थीं।

राष्ट्रपति महोदया का पहली जुलाई का कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहा। राष्ट्रपति महोदया ने तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार करीब 52 एकड़ में निर्मित महायोगी गुरू गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण कर उसे जनता को समर्पित किया। बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरखपुर में स्थापित गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्वास्थ्य संबंधी इस

महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
लोकार्पण
द्वारा
श्रीमती द्रौपदी मुर्मु

विश्वविद्यालय की स्थापना से गोरखपुर को चार यूनिवर्सिटी का गौरव भी हासिल हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में गोरखपुर विश्व स्तरीय मानक के अनुरूप हो गया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय में पढ़े हुए भारी संख्या में विशेषज्ञ डॉक्टर भी देश को उपलब्ध होंगे। भारत की उत्तम स्वास्थ्य सेवा का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, उसमें गोरखपुर का बड़ा योगदान होना गौरव की बात है।

भारत के विकास में गोरखपुर का है खास योगदान

गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा और इसमें गोरखपुर का खास योगदान होगा, क्योंकि मैं देख रही हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यह शहर स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में काफी आगे है। राष्ट्रपति महोदया ने अपनी बात शुरू करने के पहले गोरखनाथ की तपोभूमि को नमन करते हुए उनका स्मरण किया। कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली महापुरुष भारत में दोबारा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जब किसी पवित्र, पूज्यनीय और प्रभावशाली महात्मा के नाम पर कोई संस्था स्थापित होती है तो उसे आगे बढ़ने और उसके विकास को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई व्यवधान सामने नहीं टिक सकता। यही वह अदृश्य शक्ति है जो गुरु गोरखनाथ के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय को समृद्धि, प्राचीन परंपराओं को आधुनिक केंद्र के रूप में आगे बढ़ाएगा।

राष्ट्रपति ने समझाया आयुर्वेद का महत्व

गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण के दौरान राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा आदि के भारत के पुरातन चिकित्सा प्रणालियों में स्वस्थ रहने की वैज्ञानिक पद्धति बताई गई है। उन्होंने कहा कि सौ वर्ष से अधिक आयु तक भी सभी इंद्रियों को समर्थ बनाए रखने में चिकित्सा विज्ञान की प्राचीन विधियां प्रमाणित करती हैं कि इन पर आधारित पारंपरिक जीवन शैली बहुत अच्छी थी। उन्होंने आयुर्वेद के महत्व को भी समझाया। कहा कि इसे पहचानने की जरूरत है।ये औषधियां हमारे आस पास मौजूद हैं। खेतों व जंगलों में जड़ी बूटियों का खजाना है। आयुर्वेद धरती से जुड़ा है। इससे बनी औषधियों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती लिहाजा ये कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती।

पीएम मोदी का सपना साकार हुआ : योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से संपूर्ण निरोगी होने के लिए बनाया गया है। मोदी जी के सपनों को साकार करता हुआ यह उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। लोगों को आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग, नेचुरोपैथी, सिद्धा आदि विधाओं की चिकित्सा सेवा का लाभ मिलेगा। यह विश्वविद्यालय आयुष के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बड़े केंद्र के रूप में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा इस आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण बहुमुखी विकास की दृष्टि से किया गया है, जहां किसान और नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होगा। इस विश्वविद्यालय के जरिए औषधीय पौधों की खेती से किसान अच्छा पैसा कमा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भारत की आयुर्वेद की प्राचीन विधियों, सुविधाओं को वैश्विक मान्यता नहीं मिल पाई थी। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्धा को मिलाकर आयुष मंत्रालय बनाया तथा परंपरागत और प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों को विकसित करने के लिए एक नया मंच दिया। ◆

सर्वोच्च प्राथमिकता, सेहत सड़क और किसान

–चित्रांशी

गरीबों और जरूरतमंदों को इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड सरकार द्वारा प्रदत्त बड़ा हथियार है लेकिन इसमें अभी तेजी की जरूरत है ताकि यह हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके, जिसे इसकी जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे महसूस करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। महंगे अस्पताल और महंगी दवा से गरीब का इलाज मुश्किल है। गरीबों के इस दर्द से वाकिफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी जनता दर्शन में होते हैं तो उनका सारा ध्यान उन गरीबों पर होता है, जो इलाज में मदद हेतु उनके पास आते हैं। योगी सरकार और उनसे पहले के मुख्यमंत्रियों में फर्क यही है कि पहले गरीबों की कोई नहीं सुनता था, वे सिर्फ वोट के लिए होते थे। अब सीधे न केवल उनकी बात सुनी जाती है, बल्कि समाधान भी होता है।

पिछले दिनों गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में योगी के समक्ष इलाज कराने के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने वालों की भीड़ थी। योगी जी गरीबों की इस त्रासदी से वाकिफ थे ही सो उन्होंने बिना देर किए फरियादियों से कहा कि आप सभी लोग आयुष्मान कार्ड का लाभ क्यों नहीं लेते? यह योजना इसीलिए है कि एक दो या सौ पचास लोगों की मदद से अच्छा है सभी का आयुष्मान कार्ड हो ताकि वे बेफिक्र होकर महंगे से महंगा इलाज बिना चिंता फिक्र के करा सकें। केंद्र सरकार की यह मात्र सुविधा नहीं, स्वास्थ्य को लेकर जनांदोलन है।

मुख्यमंत्री ने सभी जरूरतमंदों को आश्वस्त किया कि वे बिना चिंता किए अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज कराएं। सभी जरूरतमंदों के इलाज में सरकार भरपूर आर्थिक मदद देगी। आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को पुनः निर्देशित करते हुए कहा कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और उन्हें इलाज में सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनके एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा यदि सभी के पास आयुष्मान कार्ड हो जाय तो इलाज के लिए नेताओं का चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने स्वास्थ्य महकमे को निर्देश दिए कि न्याय पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएँ।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल को बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को लंबी और आरामदायक यात्रा के लिए बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को दी गई इस सौगात से दशकों से पूर्वांचल की राजनीति में कुंडली जमाए माफिया राजनीतिज्ञों को चेताया है कि वे यदि जनहित का ख्याल रखते तो यह काम बहुत पहले ही हो जाता लेकिन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनकी प्राथमिकता में ''डेवलपमेंट नहीं डी कंपनी'' रहा करती है।

वे कहते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है और इसीलिए हम इस अंचल को रफ्तार और सुलभ यातायात की सौगात देने जा रहे हैं।गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे ऐसा ही होगा जहां राइडिंग क्वालिटी (सवारी की गुणवत्ता) और राइडिंग कम्फर्ट (आराम) विश्व स्तरीय है। यह हम नहीं कह रहे हैं। हमने तो इस सड़क निर्माण में लगे इन्जीनियरों पर भरोसा किया और वे हमारे भरोसे पर खरे उतरे। स्विटरजरलैंड की ईटीएच यूनिवर्सिटी की तकनीक और उपकरणों से हुए टेस्ट में यह प्रमाणित हुआ है। इस तकनीक का इस्तेमाल हम निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस–वे में भी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे की ही तरह जल्द ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे की राइडिंग क्वालिटी और राइडिंग कम्फर्ट में सुधार किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा एक्सप्रेस–वे की राइडिंग क्वालिटी और कम्फर्ट में सुधार के लिए जांच और उसके बाद गुणवत्ता में सुधारात्मक उपाय की अभिनव पहल की गई है। इसके लिए वाइब्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ईटीएच यूनिवर्सिटी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और इसी यूनिवर्सिटी की स्वतंत्र कंपनी (स्पिन ऑफ कंपनी) आरटीडीटी लैबोरेटरी एजी की तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। इसके अंतर्गत वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी एंड एक्सीलरोमीटर बेस्ड 7 सेंसर (4 राइडिंग क्वालिटी और 3 राइडिंग मोशन के लिए), एस मोशन सेंसर, मेजरमेंट और डाटा कलेक्शन के आवश्यक उपकरण इनोवा वाहन में स्थापित किए गए।

यूपीडा ने इस तकनीक से प्रदेश के सभी एक्सप्रेस–वेज के प्रत्येक लेन की राइडिंग क्वालिटी और राइडिंग कम्फर्ट सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण जांच तथा सुधारात्मक उपाय करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद फोर लेने की जांच पूर्ण की जा चुकी है और प्राप्त मूल्यांकित आंकड़ों और परिणाम के आधार पर राइडिंग क्वालिटी एवं राइडिंग कम्फर्ट में यथोचित सुधार कर इसे विश्व स्तरीय बना लिया गया है। यूपीडा स्विट्जरलैंड की इस तकनीकी का प्रयोग निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस–वे की सिक्स लेन पर निर्माण के दौरान कर रहा है।

अब मूंगफली होगी निर्यात योग्य फसल

मूंगफली गरीबों का बादाम कहा जाता है। इसका उपयोग रोजमर्रा के नाश्ते के साथ व्रत और तीज त्यौहार में भी खूब होता है। मूंगफली में प्रति सौ ग्राम में 567 ग्राम कैलोरी, 25 ग्राम उच्च्य गुणवत्ता प्रोटीन, 49 ग्राम असंतृप्त वसा, 7–8 ग्राम संतृप्त वसा, 16–18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 8–9 ग्राम फाइबर पाया जाता है। इसमें विटामिन ई बी 3, बी 9, के साथ–साथ मैग्नीशियम, पोटैशियम, फास्फोरस और जिंक जैसे खनिज भी मौजूद हैं।

प्रदेश के पश्चिमी हिस्से की यह प्रमुख पैदावार है। योगी सरकार ने इस फसल को निर्यात योग्य फसल के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013 से 2016 के बीच पूरे देश में मूंगफली उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान केवल दो प्रतिशत यानी यहां मूंगफली का उत्पादन मात्र एक मिलियन टन ही था। बीते दशक में राज्य सरकार की योजनाओं और तकनीकी सहायता से यह आंकड़ा करीब ढाई गुना बढ़ चुका है। अब प्रदेश का योगदान देश के कुल मूंगफली उत्पादन में 4.7 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

प्रदेश के पश्चिमी हिस्से की यह प्रमुख पैदावार है। योगी सरकार ने इस फसल को निर्यात योग्य फसल के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013 से 2016 के बीच पूरे देश में मूंगफली उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान केवल दो प्रतिशत यानी यहां मूंगफली का उत्पादन मात्र एक मिलियन टन ही था। बीते दशक में राज्य सरकार की योजनाओं और तकनीकी सहायता से यह आंकड़ा करीब ढाई गुना बढ़ चुका है।

बुंदेलखंड क्षेत्र को मूंगफली उत्पादन का बड़ा क्षेत्र माना गया है। इसके आसपास के जिलों में भी इस फसल के उत्पादन में इजाफा होते हुए देखा गया है। इसे ध्यान में रखते हुए झांसी को प्रमुख कलस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। विश्व बैंक की सहायता से चल रही यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत मूंगफली उत्पादन के क्षेत्र में बुंदेलखंड के सात जिले झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट शामिल है। योगी सरकार के प्रयास से मूंगफली के निर्यात को नया पड़ाव मिलेगा। ऐसा होने पर मूंगफली उत्पादकों को बेहतर दाम मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। भारत में मूंगफली का सबसे बढ़िया उत्पादन गुजरात में होता है। यहां इसका उत्पादन प्रतिशत 47 है जबकि राजस्थान में 16 है। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है जहां इसका उत्पादन प्रतिशत 10 है। उत्तर प्रदेश में मूंगफली की खेती का मुख्य केंद्र बुंदेलखंड तो है ही लेकिन इसके आसपास के जिले जैसे मैनपुरी, हरदोई, इटावा, फरूर्खाबाद, कन्नौज, अलीगढ़, कासगंज, औरैया, कानपुर देहात, बदायूं, एटा, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर नगर और श्रावस्ती जिले भी प्रमुख मूंगफली उत्पादक जिले हैं। कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश मूंगफली उत्पादन में प्रति हेक्टेयर 809 किलो ग्राम ही था जबकि राष्ट्रीय औसत पर यह 1542 किग्रा प्रति हेक्टेयर है। मूंगफली उत्पादन में आश्चर्यजनक यह है कि तमिलनाडु अकेला प्रदेश है जहां मूंगफली का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 2679 किलोग्राम है। अब इस फसल के उत्पादन में आशातीत परिवर्तन यह हुआ कि यहां भी प्रति हेक्टेयर 1688 किलो ग्राम से अधिक की ऊंचाइयां छू रहा है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि योगी सरकार ने इस पर खासा ध्यान दिया है। मसलन फसल सुरक्षा, आधुनिक बीज और किसानों को दी गई तकनीकी मदद आदि।

पैदावार में बढ़ोत्तरी के साथ मूंगफली किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य भी मिलने लगा। इसके लिए योगी सरकार किसानों से एमएसपी के तहत मूंगफली की खरीद करवा रही है। इस वर्ष के मूंगफली सीजन में 6,783 रूपये प्रति क्विंटल तय की गई है। नैफेड मैनपुरी, इटावा, हरदोई में मूंगफली की खरीद करेगी जबकि एनसीसीएफ फर्रुखाबाद, कन्नौज, अलीगढ़, कासगंज, औरैया, कानपुर देहात, एटा, बदायूं, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर नगर और श्रावस्ती में किसानों से सीधे मूंगफली की खरीद कर रही है। इस तरह देखें तो यूपी में योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सेहत, सड़क और किसान है। ◆

मो. : 8795087975

पारदर्शी पुलिस भर्ती से खिले युवाओं के चेहरे

–डॉ. अजय कुमार मिश्रा

मिशन रोज़गार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा
निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित
60,244
रोज़गार
8.5 लाख+
सरकारी नौकरी

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश के किसी भी राज्य से सबसे अधिक है। भारत की कुल जनसंख्या में इसकी हिस्सेदारी लगभग 17% के करीब है। अपेक्षित वर्तमान जनसँख्या 24 करोड़ से अधिक है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि कानून व्यवस्था बनाये रखना और सभी आम निवासियों को सुरक्षा और अपने अधिकार का एहसास कराना सरकार के प्रयास से ही संभव हो पायेगा। ऐसा दो तरह से किया जा सकता है एक तो लोगों को जागरूक करके, दूसरा निश्चित आबादी पर पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करके। इन दोनों उपायों के जरिये सरकार प्रदेश में सुशासन स्थापित कर सकती है। देश के सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य होने के नाते कई विषमताएं और चुनौतियां है। प्रदेश में जगह–जगह शांति स्थापना की आवश्यकता नियमित पड़ती है और इसमें सफल न होने वाली किसी भी सरकार को जनता पुनः सत्ता में लाने से हिचकती है। जनता का प्राथमिक उद्देश्य अपनी, अपने परिवार की, अपनी संपत्ति की रक्षा करना है, तत्पश्चात् वह अन्य बिन्दुओं पर विचार करती है। क्योंकि सुरक्षा ही एक ऐसा पहलू है जिसके पश्चात स्वतंत्र रूप से किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए जनता कार्य करती है।

उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में सत्ता में आने पर योगी आदित्यनाथ ने इस विषय पर गहनता से अवश्य सोचा होगा। क्योंकि विगत आठ वर्षों में उनके द्वारा इस बिंदु पर किये गए सजीव और जीवंत प्रयासों ने न केवल रोजगार के द्वार खोले हैं बल्कि करोड़ों की आबादी को निश्चिन्तता भी प्रदान की है। यह अत्यधिक प्रभावशाली तथ्य है कि अपने पूर्व की सरकार को इस विषय में उन्होंने काफी पीछे भी छोड़ दिया है। प्रदेश में रोजगार के लिए युवा अत्यधिक आशावादी दृष्टि से योगी आदित्यनाथ को सत्ता में आने के पश्चात् देख रहा था, ऐसे में उन सभी की आशाओं पर खरा उतरते हुए अकेले पुलिस विभाग में 1 अप्रैल, 2017 से लेकर 1 जून, 2025 के मध्य पुलिस विभाग में कुल 2,18,262 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर न केवल रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया बल्कि सुरक्षा के नए आयाम को भी स्थापित कर दिया है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा ने प्रदेश सरकार पर पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में उठे सवालों को चुनौतीपूर्ण लेते हुए सफल और पारदर्शी पुलिस भर्ती करके सभी को न केवल चौंकाया है बल्कि सबसे बड़ी भर्ती विवाद रहित करके प्रदेश का न केवल मान–सम्मान बढ़ाया बल्कि उस कयासों से मुक्ति दिलाई जिसमें यह कहा जाता रहा है सरकार की कोई भी भर्ती विवाद के बिना पूर्ण नहीं होती। उत्तर प्रदेश में 60244 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से अब प्रदेश के सभी मंडल, जिला, तहसील और ग्रामीण स्तर तक सुशासन और अधिक मजबूत होगा। अभी हाल ही में सीधी

भर्ती के जरिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता और उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजीपी राजीव कृष्णा की ईमानदारी से कार्य के प्रति प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि– आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 के परिणाम में 60244 नियुक्ति की गई है। रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक सीधी भर्ती– 2022 जिसका परिणाम 26 मार्च, 2025 को जारी हुआ इसमें 1374 लोगों की भर्ती की गई है। रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी सीधी भर्ती– 2022 जिसका परिणाम 26 मार्च, 2025 को जारी हुआ इसमें 120 लोगों की भर्ती की गई है। यानि कि वर्तमान वर्ष में 61,738 लोगों को अकेले पुलिस विभाग में नियुक्ति देना बड़ी उपलब्धियों में से एक है। ये नियुक्तियां न केवल रोजगार के अवसरों की पूर्ति कर युवाओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर कहती हैं कि सरकार हमारी है जो हमारे बारे में गंभीरता से सोचकर कार्य करती है बल्कि यह भी एहसास दिलाती है कि आम जन की सुरक्षा प्रदेश की सरकार के लिए सर्वोपरि है।

जनता की आशाओं और उम्मीदों की पूर्ति अक्सर चुनावी एजेंडा बन कर रह जाती है और चुनाव हो जाने के पश्चात् उसे सरकारें ठन्डे बस्ते में डाल देती थीं या यूँ कहें सत्ता में आने के पश्चात जनता को दिखाए गए विकास की तस्वीर को पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान रोक दिया जाता था और जनता हमेशा ठगा हुआ महसूस करती थी। योगी सरकार ने सत्ता में आने के पश्चात् से ही किये गए वायदों की पूर्ति को प्रथम स्थान पर रखा है और प्रत्येक छोटी बड़ी बातों का संज्ञान लेकर जमीनी स्तर पर कार्यवाही प्रत्येक क्षेत्र और विभाग में लगातार की जा रही है।

यदि देखा जाय तो पूर्व की सरकार वर्ष 2012 से 31 मार्च, 2017 के मध्य महज 49,965/– नियुक्ति ही पुलिस विभाग में कर पायी थी। भर्ती प्रक्रिया पर भी कई सवाल उस समय उठे थे। पूर्व सरकार से लगभग पांच गुना अधिक भर्ती अकेले पुलिस विभाग में करके उसे धरातल पर लाकर योगी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता से जनता को अवगत कराया है, जिसका उद्देश्य आमजन की सुरक्षा,

अपराध और अपराधियों का खात्मा करना और अपनी जीरो टोलरेंस नीति के तहत लगातार कार्य करना शामिल है। योगी सरकार ने नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के कार्यक्रम को लखनऊ में बड़े पैमाने पर आयोजित कर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह से नियुक्ति पत्र वितरित करवा करके पूरे देश को अपने निस्वार्थ भाव और जनता के प्रति अपने समर्पण का सीधा सन्देश दिया है। इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र वितरण के कार्य में कोई भी खामियां देखने को नहीं मिलीं जबकि नियुक्त युवाओं को उनके गृह जनपद से लाने और वापस पहुँचाने तक का सारा जिम्मा राज्य सरकार ने लिया था। यह प्रतिबद्धता और कठिन परिश्रम ही है कि युवाओं में बड़ा जोश देखने को मिल रहा है और जनता योगी के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट कर रही है।

जनता की आशाओं और उम्मीदों की पूर्ति अक्सर चुनावी एजेंडा बन कर रह जाती रही है और चुनाव हो जाने के पश्चात् उसे सरकारें ठंडे बस्ते में डाल देती थीं या यूँ कहें कि सत्ता में आने के पश्चात जनता को दिखाई गई विकास की तस्वीर को पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान रोक दिया जाता था और जनता हमेशा ठगा हुआ महसूस करती थी। योगी सरकार ने सत्ता में आने के पश्चात् से ही किये गए वायदों की पूर्ति को प्रथम स्थान पर रखा। प्रत्येक छोटी बड़ी बातों का संज्ञान लेकर जमीनी स्तर पर कार्रवाई प्रत्येक क्षेत्र और विभाग में लगातार की जा रही है। पांच वर्ष के बाद हुए चुनाव में जनता द्वारा योगी सरकार पर पुनः भरोसा दिखाने के पीछे कठिन परिश्रम और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करना मुख्य कारण रहा है। ऐतिहासिक पुलिस भर्ती करके योगी आदित्यनाथ ने जनता को दिए अपने आश्वासन को सजीव कर दिया है कि प्रदेश में अब अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। योगी की पुलिस हर परिस्थिति का सामना करने में अब आधुनिक तकनीकी और संख्या बल के साथ मजबूती से उपस्थित है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा जो पुलिस रिक्रूटमेंट को सीधे देख रहे थे, उन्होंने पारदर्शी भर्ती योग्यता के आधार पर

नियुक्ति करके यह भी साबित कर दिया है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी प्रतिकूल हों सफल होने और लोगों के पूर्ववर्ती विचारों को अपने कार्य के बूते बदला जा सकता है।

रोजगार सृजन की इस बड़ी उपलब्धि, विवाद रहित नियुक्ति, सुरक्षा के प्रति की गयी बड़ी नियुक्ति, देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य के प्रत्येक नागरिकों के हितों की रक्षा के प्रति योगी सरकार का समर्पण जमीनी स्तर पर सभी को दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि दिन–प्रतिदिन योगी की लोकप्रियता आम जन में प्रदेश के बाहर, देश के बाहर तक तेजी से बढ़ रही है। यह योगी आदित्यनाथ की ही सोच है जिसके जरिये युवाओं के चेहरे पर रोजगार से मुस्कान लाने में सफल है और यह मैसेज सभी को दे रही है कि वास्तव में नेतृत्वकर्ता सजग और प्रतिबद्ध हों तो करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरा जा सकता है। ◆

मो. : 9335226715

उच्च शिक्षा-उच्च गुणवत्ता का संकल्प

—सुरेन्द्र अग्निहोत्री

आज का परिवेश दिनों—दिन प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है, ऐसे में युवाओं को शिक्षा व करियर में आने वाली चुनौतियों से निपटने में आधुनिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता युक्त शिक्षा से सम्भव हो सकता है। उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों का उद्देश्य होगा उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा बनाना है, जो जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति कर देश प्रदेश और अपना नाम रोशन कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा आईसीटी का उपयोग कर प्रदेश की उच्च शिक्षा को नई पहचान मिल रही है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में छात्रों और शिक्षकों को न सिर्फ भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाया गया, बल्कि इसके अनुरूप तैयार भी किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग भविष्य की चुनौतियों के अनुसार उच्च शिक्षा के पठन—पाठन को विकसित करने के लिए वचनबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहां वे विश्व स्तरीय शिक्षा और संसाधनों का लाभ उठाकर अपने करियर को नई दिशा दे सकें।

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा को डिजिटल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। छात्रों को टैबलेट और मोबाइल वितरित किए गए। प्रयागराज में ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई—स्टूडियो की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, 41 लाख से अधिक छात्र अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में पंजीकृत हो चुके हैं, और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 'समर्थ—ई.आर.पी.एस. प्रणाली लागू की जा चुकी है। इसके साथ ही, उच्च शिक्षा संस्थानों में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र

स्थापित किए गए हैं। स्थानीय भाषाओं में ई–सामग्री तैयार की जा रही है, ताकि शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया जा सके।

भारतीय संस्कृति और परम्पराओं को छात्रों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रत्येक विषय की पहली इकाई में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को भारत की प्राचीन कला, संस्कृति और विज्ञान से परिचित कराया जा सके। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान कई निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय और कॉलेजों की स्थापना के प्रति रुचि दिखाई, जो प्रदेश को शैक्षिक हब के रूप में उभरते हुए देख रहे हैं। शोध कार्यों के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को 57.38 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। यह अनुदान प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध कार्यों की गुणवत्ता में सुधार और नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदान किया गया है।

> **उच्च शिक्षा मंत्री, योगेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग भविष्य की चुनौतियों के अनुसार उच्च शिक्षा के पठन–पाठन को विकसित करने के लिए वचनबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहां वे विश्व स्तरीय शिक्षा और संसाधनों का लाभ उठाकर अपने करियर को नई दिशा दे सकें।**

उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि शोध और अनुसंधान शिक्षा का आधार स्तम्भ हैं। प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य के विश्वविद्यालयों में शोध और नवाचार को गति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे हमारे शिक्षण संस्थानों में न केवल शोध की दिशा में नई ऊर्जा का संचार होगा, बल्कि छात्रों को भी विश्वस्तरीय शोध वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में यह अहम कदम है। जिन विश्वविद्यालयों को अनुदान प्राप्त हुआ है, उनमें

लखनऊ विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय (बरेली), महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ (वाराणसी), वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय (जौनपुर) और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय (कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर) शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए इस योजना के अन्तर्गत कुल 57,38,800 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है, जो निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन वितरित की जाएगी।

प्रदेश की उच्च शिक्षा में यह अनुदान मील का पत्थर साबित होगा। हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी शोध केंद्र बनाया जाए। यह अनुदान उस दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

असेवित जनपदों में विश्वविद्यालय खोलने के लिए नई पॉलिसी

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने हेतु असेवित जनपदों में जहाँ कोई विश्वविद्यालय नहीं है, वहाँ पर नई पॉलिसी तैयार की गई है। भारत के टॉप विश्वविद्यालयों तथा विदेशी विश्वविद्यालयों को उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय खोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय खोलने में प्रदेश सरकार अनेक सुविधाएं एवं सहायता प्रदान कर रही है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर न जाना पड़े और उत्तर प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए

अधिक विकल्प मिलें उत्तर प्रदेश में विदेशी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का हब बनेगा, जिससे विदेशी छात्र भी उत्तर प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करने आयें।

> **उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा को डिजिटल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। छात्रों को टैबलेट और मोबाइल वितरित किए गए हैं और प्रयागराज में ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई–स्टूडियो की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, 41 लाख से अधिक छात्र अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में पंजीकृत हो चुके हैं, और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में ‘समर्थ–ईआरपी, प्रणाली लागू की जा चुकी है।**

योगी सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके तहत योगी सरकार प्रदेश के 8 प्रमुख विश्वविद्यालयों में कुल 58 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने जा रही है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बढ़ावा देना है, जिससे छात्रों और शिक्षकों को न सिर्फ भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाया जा सके, बल्कि इसके अनुरूप तैयार भी किया जा सके। इसके लिए सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए विश्वविद्यालयों को कुल 03 करोड़ 88 लाख 77 हजार 8 सौ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस धनराशि से छात्रों और शिक्षकों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

सरकार प्रदेश के विश्वविद्यालयों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना से न केवल छात्रों को शोध और तकनीकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में नई संभावनाएं मिलेंगी, बल्कि विश्वविद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा। ''सेंटर ऑफ एक्सीलेंस'' योजना के तहत प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ और छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर को शामिल किया गया है।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रोजेक्ट फेलो के साथ–साथ अत्याधुनिक शोध उपकरण, पुस्तकालयों का विकास और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के क्रियान्वयन, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग, क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचार–प्रसार और भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) को उच्च शिक्षा में एकीकृत कर अपनाया है। ◆

मो. : 9415508695

उत्तर प्रदेश : रोजगार प्रदेश
भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती पर युवाओं को भरोसा

–रजनीश वैश्य

निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से उत्तर प्रदेश के लाखों परिवारों की जिन्दगी बदल रही है। भर्ती प्रक्रिया ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज कर रही है। आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती में 60,244 युवाओं को एक साथ नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। खास बात यह रही कि पुलिस में नियुक्ति पाने वालों में सिर्फ उत्तर प्रदेश के युवा ही नहीं, बल्कि देश के कई अन्य राज्यों के युवा भी शामिल रहे। राजधानी लखनऊ का डिफेंस एक्सपो ग्राउंड उस ऐतिहासिक दृश्य का गवाह बना, जब पहली बार राज्य में एक साथ हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस विशाल नियुक्ति समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में हजारों नवनियुक्त आरक्षियों ने नई जिन्दगी में कदम रखा। एक तरफ उनके लिए लाखों खुशियां थीं तो बड़ी जिम्मेदारी भी। इन युवाओं में हजारों ऐसे भी रहे, जिनके परिवार में पहली बार किसी को भी सरकारी नौकरी का सौभाग्य मिला था।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में अब प्रतिभा की पहचान है। जाति–पाति और भेदभाव के आधार पर नौकरी के लिए चयन काफी पुरानी बात हो चुकी है। भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती पर प्रदेश के युवाओं को भरोसा है। यह भर्ती 'सबका साथ, सबका विकास' के संकल्प को साकार कर रही है। न खर्ची, न पर्ची, न सिफारिश, न जातिवाद, केवल योग्यता के आधार पर 60,244 युवाओं की भर्ती होना, उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि है। युवा हृदय सम्राट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में सबको रोजी–रोटी है। प्रदेश में इस पर सबका समान अधिकार है। राज्य में 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा जा चुका है। 3.75 लाख संविदा पर नौकरी कर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई इकाइयों का विशाल आधार है। निजी क्षेत्र व एमएसएमई से 2 करोड़ से अधिक लोग जुड़कर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में 2.16 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हो चुकी है। इसमें बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की भी है। 27,178 महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति कर प्रदेश में महिला सुरक्षा पर फोकस किया गया है। प्रदेश में 1.64 लाख से अधिक पदों पर पुलिसकर्मियों की भर्ती पूरी हो चुकी है। आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती में 12,048 महिलाओं का चयन किया गया है।

तकनीक से पारदर्शिता

भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया रहा है। तकनीक के उपयोग से शुचितापूर्ण तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो रही है। भर्ती प्रक्रिया जनमानस का विश्वास जीतने में कामयाब हो रही है। गोपनीयता एवं पारदर्शिता के साथ सुदृढ़ सुरक्षा तंत्र एवं निगरानी ढांचे के मध्य सम्पन्न भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती हैं। परीक्षा केंद्रों तथा स्ट्रांग

रूम में 24x7 सीसीटीवी कवरेज की व्यवस्था, अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निगरानी की व्यवस्था भी की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेस रिकॉग्निशन तथा बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग भी किया जा रहा है। नकल माफिया, सॉल्वर गैंग तथा पेपर लीक करने की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर उनको खोखला कर दिया गया है। प्रदेश में पूर्ण ईमानदारी के साथ परीक्षा पैटर्न को बदलने का कार्य किया गया है। सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, 2024 लागू है, जिसमें नकल माफिया, सॉल्वर गैंग तथा पेपर लीक करने की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की व्यवस्था है।

ऐतिहासिक आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती

- 48,17,441 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन, अब तक के इतिहास में सर्वाधिक संख्या
- 15,48,969 महिला अभ्यर्थी भी शामिल।
- 1,74,317 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण (रिक्त के सापेक्ष लगभग 2.5 गुना)।
- अंतिम चयन परिणाम में 60,244 अभ्यर्थियों का चयन (48,196 पुरुष, 12,048 महिला)।
- 67 जनपदों में अविवादित 1,174 परीक्षा केंद्रों के माध्यम से निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 60,244 अभ्यर्थियों का चयन।
- 75 जनपदों में 100 समितियों के माध्यम से लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन एवं शारीरिक मानक परीक्षण डेढ़ माह में सम्पन्न।
- उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य प्रदेशों (बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल) से भी अभ्यर्थियों का चयन।

सपने हो रहे साकार
8.5 लाख+
3.75 लाख+

सपने हो रहे साकार
8.5 लाख+
3.75 लाख+

उत्तर प्रदेश में नियुक्ति प्रक्रिया

वर्ष 2017 से पूर्व :

- विवादों में रहती थी नियुक्ति प्रक्रिया।
- सरकारी नौकरी में हावी था भाई–भतीजावाद।
- बैक डोर से नियुक्ति प्रक्रिया सामान्य बात।
- नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नियुक्ति पत्र प्राप्त होने में भी लंबा समय लगता था।
- न्यायालयों के हस्तक्षेप के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ पाती थी।

वर्ष 2017 के बाद :

- निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से नियुक्तियां।
- भर्ती प्रक्रिया से लेकर नियुक्ति पत्र वितरण तक की प्रक्रिया में कहीं भी सिफारिश की आवश्यकता नहीं।
- सबके लिए समान रूप से नौकरी की राह आसान।
- नकलविहीन परीक्षाएं, सख्त सुरक्षा प्रबंध, तकनीक का उपयोग।

रोजगार के नए अवसरों का सृजन

उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जा रहा है। उनका कौशल विकास कर तकनीकी ज्ञान से सम्पन्न किया जा रहा है। इंडस्ट्री के नए उभरते क्षेत्रों जैसे एआई व रोबोटिक्स आदि का प्रशिक्षण भी युवाओं को दिया जा रहा है। प्रदेश में निवेश का वातावरण सृजित होने तथा उद्योग–धंधे का माहौल विकसित होने से भी रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जीबीसी और सेमीकॉन इंडिया

जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों से प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना से टैबलेट/स्मार्टफोन से 2 करोड़ युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे वे हाईटेक पढ़ाई की ओर उन्मुख हो सकें। डिजिटल प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा अपने कौशल से समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान देंगे।

समृद्ध नारी उत्तर प्रदेश की पहचान

उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर मुख्य फोकस है। प्रदेश में लगभग 1.5 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया है। 1 लाख के करीब स्वयं सहायता समूहों से 1 करोड़ महिलाएं उन्नति की राह तय कर रही हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किया गया है। 58,000 महिलाओं का चयन बीसी सखी के लिए किया गया है। बीसी सखी गांवों में बैंकिंग सुविधाओं को जन–जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। कामकाजी महिलाओं की मूलभूत सुविधाओं का भी राज्य में विशेष ध्यान रखा जा रहा है। रात्रि में आवश्यकतानुसार महिलाओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एस्कॉर्ट की व्यवस्था की गयी है।

विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी

उत्तर प्रदेश सरकार ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों पर न सिर्फ धनवर्षा कर रही है, बल्कि उनको राजपत्रित पदों पर सीधे नियुक्त भी कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा करीब 500 खिलाड़ियों की भर्ती पुलिस सेवा में की गयी है। इससे पुलिस बल को नयी ऊर्जा और प्रेरणा मिल रही है।

स्वरोजगार ही राह आसान

योगी सरकार ने युवाओं के लिए स्वरोजगार की राह भी आसान की है। युवाओं को रुचि के अनुसार प्रशिक्षण देकर उनके कौशल को निखारा जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उनको उदार शर्तों पर वित्तीय मदद प्रदान की जा रही है। अभियान चलाकर ऋण मेला आयोजित कर ऋण वितरण किया जा रहा है तो रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार के अवसर सुलभ कराए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के हर जिले के उत्पाद की अपनी विशिष्ट पहचान है। इन उत्पादों और इससे जुड़े कारीगरों /शिल्पकारों को वैश्विक मंच ओडीओपी कार्यक्रम के माध्यम से मिला है। इनसे जुड़े शिल्पकारों का हुनर निखारने के लिए योगी सरकार 1.0 में शुरू की गई यह योजना इतनी चर्चित रही है कि केंद्र सरकार ने भी इसे अंगीकृत किया है। इससे स्थानीय स्तर पर लाखों लोगों को रोजगार मिला है।

परम्परागत कारीगरों जैसे नाई, धोबी, दर्जी, लोहार, बढ़ई, मोची और टोकरी बनाने वालों के लिए योगी सरकार के पहले कार्यकाल में (विश्वकर्मा श्रम सम्मान) योजना प्रारंभ की गयी थी। योजना में कारीगरों के हुनर में चार चांद लगाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको अपने जीविकोपार्जन में आसानी रहे, इसके लिए उनको टूलकिट भी वितरित किया जाता है। इस योजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। रोजगार के अवसरों में भी विस्तार हो रहा है।

रोजगार अपार

- सरकारी नौकरी : 8.50 लाख।
- संविदा पर नौकरी : 3.75 लाख।
- निजी क्षेत्र/एमएसएमई में रोजगार : 2 करोड़।
- 10 लाख स्वयं सहायता समूह से 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार।
- 58,000 महिलाओं को बीसी सखी योजना से रोजगार।
- 30 लाख शिल्पकारों/कामगारों को ओडीओपी से रोजगार।
- 5 लाख युवाओं को स्टार्टअप नीति के अंतर्गत रोजगार।
- राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेता खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती।

मो. : 8840973541

बेहतर यातायात की धुरी बने एक्सप्रेस-वे

–प्रदीप उपाध्याय

ढांचागत सुविधाओं का विकास हो या फिर औद्योगिकीकरण, इनके लिए जमीन की पर्याप्त जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश में विकास के नए युग का सूत्रपात हुआ है। लोग अपनी जमीनें दे रहे हैं लिहाजा नए हवाई अड्डे बन रहे हैं। एक्सप्रेस वे का सघन जाल बुना जा रहा है। लखनऊ, नोएडा, कानपुर आदि शहरों में मेट्रो ट्रेन से लोग सफर कर रहे हैं। अन्य कई जिलों में मेट्रो के निर्माण का कार्य तेजी के साथ संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही परम्परागत तीर्थस्थलों का भी तेजी के साथ विकास हो रहा है। एक ओर जहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण राज्य के वैभव को द्विगुणित कर रहा है वहीं काशी कॉरिडोर ने वाराणसी के सौंदर्य को नयी आभा प्रदान की है। कुशीनगर समेत बौद्ध परिपथ से जुड़े सभी प्रमुख स्थलों का योजनाबद्ध विकास एवं सुंदरीकरण कराया जा रहा है। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के सुंदरीकरण की भव्य योजना लगभग तैयार है। इस मार्ग में जो छिटपुट विधिक अड़चनें और अन्य दिक्कतें हैं, उनका भी समयोचित समाधान किया जा रहा है। राज्य के तमाम जिलों में सड़कों की मरम्मत का काम बड़े पैमाने पर संचालित किया जा रहा है। टू–लेन सड़कों को फोर लेन में तब्दील किया जा रहा है। फोर लेन सड़कें सिक्स लेन बन रही हैं। नए एक्सप्रेस–वे संचालित किए जा रहे हैं। दशकों पूर्व उत्तर प्रदेश की हिंदी पट्टी के बीमारू राज्यों के रूप में गिनती होती थी। अब नया उत्तर प्रदेश न सिर्फ देश के नक्शे पर तेजी के साथ उभर रहा है बल्कि विकास के समस्त प्रचलित मानकों पर देश के विकसित राज्यों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करता हुआ भी नजर आ रहा है। वह अपनी नयी पहचान बना रहा है और कामयाबी की नयी इबारत लिख रहा है। ऐसा प्रदेश के सक्षम एवं दूरदर्शी नेतृत्व के कारण संभव हो सका है जिसकी कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में हैं।

गत दिनों वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे जनता को समर्पित किया। इसका उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले पता ही नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है या कि गड्ढे में सड़क । उनका कहना गलत नहीं था। एक दशक पहले राज्य की अधिकांश सड़कें बदहाल दशा में थी। अब सड़कों के न सिर्फ निर्माण बल्कि रखरखाव पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है इससे प्रदेश की सूरत बदली है। सड़क यातायात सुगम और आरामदेह बनता जा रहा है। आप सुकून और इत्मिनान के साथ अपने वाहन या सार्वजनिक वाहन से राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक आवागमन कर सकते हैं। यह बदलाव सुदूर पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण अथवा मध्यवर्ती इलाकों में आप समान रूप से महसूस कर सकते हैं।

आजमगढ़ से गोरखपुर के मध्य लगभग इक्यानबे

किलोमीटर लम्बा यह लिंक एक्सप्रेस–वे 7,283 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह एक्सप्रेस–वे आजमगढ़ के साथ–साथ अम्बेडकरनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर सरीखे पूर्वी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों को विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे काशी, लखनऊ, आगरा एवं दिल्ली तक तीव्र यातायात कॉरिडोर विकसित होगा और पूर्वांचल के विकास को नयी गति मिल सकेगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) का सातवां संचालित एक्सप्रेस–वे बन गया है। उत्तर प्रदेश में यूपीडा द्वारा संचालित एक्सप्रेस–वे हैं– पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे, यमुना एक्सप्रेस–वे, दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस वे, नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस–वे और अब गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। इन सात एक्सप्रेस वे में पांच का निर्माण विगत आठ वर्षों के दौरान योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ है। **मौजूदा समय में तीन एक्सप्रेस–वे निर्माणाधीन हैं जबकि आठ एक्सप्रेस–वे का निर्माण होना प्रस्तावित है।** योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में भी विकसित हुई है। 2017 से पहले यूपी में सिर्फ दो एक्सप्रेस–वे थे, जबकि पिछले आठ साल में पांच नए एक्सप्रेस–वे विकसित किए गए। इससे राज्य के भूतल परिवहन को नयी ताकत हासिल हुई है। यह नए और पुराने एक्सप्रेस वे प्रदेश के विकास को नयी रफ्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश में आवाजाही सुगम हुई है। पर्यटन और उद्योग धंधों के विकास को नयी गति एवं सुगमता प्राप्त हुई है।

पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है। इसकी लम्बाई 341 किलोमीटर है। जबकि चित्रकूट से इटावा तक आने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे 296 किलोमीटर लम्बा है। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे आगरा से लखनऊ तक विस्तार लिए हुए है। इसकी कुल दूरी 302 किलोमीटर है। प्रदेश के इस पहले एक्सप्रेस–वे पर जब काम शुरू हुआ था तब राज्य में मायावती के नेतृत्व में बसपा सत्तारूढ़ थी। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तब इस एक्सप्रेस वे का लोकार्पण हुआ था। इसकी तकनीक इतनी उन्नत है कि इस पर फाइटर प्लेन तक उतारे जा सकते हैं। इस एक्सप्रेस–वे पर अनेक एयर शो आयोजित किए जा चुके हैं। यमुना एक्सप्रेस–वे ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच बनाया गया है। यह दूरी 165 किलोमीटर की है। दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे दिल्ली से मेरठ के बीच बनाया गया है। इससे एनसीआर के विकास को नयी उड़ान हासिल हुई है। दिल्ली से मेरठ के बीच 82 किलोमीटर में फैले इस अत्याधुनिक एक्सप्रेस–वे ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास की नयी इबारत लिखनी शुरू की है। नोएडा एक्सप्रेस–वे नोएडा से ग्रेटर नोएडा के 25 किलोमीटर की दूरी तक विकसित किया गया है। इसने भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास को नयी गति प्रदान की है।

उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे के निर्माण पर 22,494 करोड़ की धनराशि का व्यय हुआ था। जबकि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे के बनने में 13,200 करोड़ की लागत आई थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे के निर्माण पर 14,850 करोड़ का खर्च आया। इसी प्रकार यमुना एक्सप्रेस–वे के निर्माण पर 13,300 करोड़ व्यय हुए। अभी

हाल में बने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे के निर्माण पर 7,283 करोड़ की लागत आई। इससे गोरखपुर से लखनऊ का सफर मात्र तीन घंटे में पूरा किया जा सकेगा। पहले यह दूरी तय करने में आम तौर पर साढ़े तीन से चार घंटे लग जाया करते थे। अपनी जमीन देकर रोड कनेक्टिविटी की इस शानदार परियोजना को साकार करने वाले किसानों को खुशहाल बनाने में राज्य सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस परियोजना के लिए सरकार ने 22,029 किसानों को 2030 करोड़ 29 लाख रुपए का मुआवजा दिया। यही नहीं जमीन देने वाले किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परियोजना के शुरुआती चरण में सम्मानित करके उनके अहम योगदान की भरपूर सराहना कर चुके हैं। यूपी के किसान यह भली भांति जानते हैं कि ढांचागत सुविधाओं का विकास हो या फिर औद्योगिक विकास; इन्फ्रास्ट्रक्चर तभी मजबूत बनेगा जब बिजली, पानी और जमीन के साथ–साथ निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर माहौल बनाया जाए। प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति में अपेक्षित सुधार होने से विकास के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल बना है। ऐसे में बेहतर सड़कों का नेटवर्क जो विभिन्न एक्सप्रेस–वे के बनने से प्रदेश के सड़क परिवहन के नक्शे को और सघन बुनावट प्रदान कर रहा है। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर की मजबूती भी बयान कर रहा है। कौन नहीं जानता कि अच्छी सड़कें होंगी तो न सिर्फ कच्चे माल की आवक सुगम होगी बल्कि तैयार माल सुदूर मंडियों में पहुंचाया जा सकेगा। न सिर्फ व्यापारी लाभान्वित होंगे बल्कि पूंजीपतियों को नया इलाका मिलेगा जहां वे अपने उद्योग धंधे विकसित कर सकेंगे। किसान अपने अनाज, फल और सब्जियों, दुग्ध आदि उत्पादों को एक से दूसरी मंडी तक पहुंचाकर बेहतर लाभ कमा सकेंगे। इसके साथ ही स्थानीय रोजगार के अनेक अवसर सहज उपलब्ध हो सकेंगे। किसान अन्नदाता होने के साथ–साथ विकास कार्यों में अहम् भूमिका निभाते हैं। किसानों को पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत मुआवजे की राशि प्रदान की जाती है। एक दौर था जब बिचौलिये सरकारी अनुदान राशि का बड़ा हिस्सा खा जाते थे, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार ने नयी कार्य संस्कृति को बढ़ावा दिया है।

उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे के निर्माण पर 22,494 करोड़ की धनराशि का व्यय हुआ था। जबकि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे के बनने में 13,200 करोड़ की लागत आई थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे के निर्माण पर 14,850 करोड़ का खर्च आया। इसी प्रकार यमुना एक्सप्रेस–वे के निर्माण पर 13,300 करोड़ व्यय हुए। अभी हाल में बने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे के निर्माण पर 7,283 करोड़ की लागत आई। इससे गोरखपुर से लखनऊ का सफर मात्र तीन घंटे में पूरा किया जा सकेगा। पहले यह दूरी तय करने में आम तौर पर साढ़े तीन से चार घंटे लग जाया करते थे। अपनी जमीन देकर रोड कनेक्टिविटी की इस शानदार परियोजना को साकार करने वाले किसानों को खुशहाल बनाने में राज्य सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।

ठेकेदारों–अफसरों और छुटभैये नेताओं का नेक्सस लगातार टूटा है। मोदी–योगी सरकार की धमक का असर है कि अब कोई सरकारी योजनाओं में निजी हिस्सेदारी और बंदरबांट के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता है। पहले के दौर में यह आम बात थी।

GANGA EXPRESSWAY GROUP

गोरखपुर से आजमगढ़ के बीच तकरीबन इक्यानबे किलोमीटर लम्बे इस एक्सप्रेस वे के लिए चार जिलों गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकरनगर और आजमगढ़ के 172 गांवों के किसानों की 1148. 77 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया थ। इसके लिए किसानों को दो हजार करोड़ रुपए से अधिक की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया था। इस परियोजना के लिए किसानों ने खुले मन से राज्य सरकार का सहयोग किया। किसी गांव से कोई शिकायत नहीं आई। जो छिटपुट शिकायतें आई भी उनका सौहार्दपूर्ण माहौल में खुली सुनवाई के अंतर्गत समाधान किया गया। जनवरी 2020 में जब गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे का निर्माण प्रारंभ हुआ तो इसके शुरुआती चरण में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में आयोजित एक समारोह के अंतर्गत जमीन देने वाले पांच सौ किसानों को सम्मानित किया था। रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जटिल माने जा रहे इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादों की झलक भी देखने को मिलती है। जब यह परियोजना वक्त बीतने के साथ–साथ आकार ग्रहण करने लगी तो इसके तात्कालिक और दूरगामी फायदों के बारे में लोगों ने चर्चा करनी शुरू कर दी। यह एक्सप्रेस–वे इंडस्ट्रियल कॉरीडोर की भी सौगात लेकर आया है। इसका किनारा निवेशकों की पसंद बन गया है। एक्सप्रेस–वे का लोकार्पण होने से पहले से ही यहां चार औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन किया जा चुका है। इनमें बाकायदा उत्पादन चल रहा है। जबकि कुछ अन्य औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे के किनारे गीडा ने अपने महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सेक्टर विकसित किए हैं। गीडा ने 88 एकड़ क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क बनाया है। इसमें प्लास्टिक उत्पाद की 92 इकाइयों के भू आवंटन की योजना बनाई है। इस दिशा में तकरीबन पांच दर्जन भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है।

154 एकड़ और 362 एकड़ में फैले दो औद्योगिक गलियारों के विकास से पूर्वांचल की नयी तस्वीर उभर कर सामने आएगी। इससे गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन का दंश झेल रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के असंख्य जिलों और कस्बों में विकास की नयी बयार बहेगी। क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार के नए विकल्प पैदा होंगे। पलायन जो इस विस्तृत भू भाग के नौजवानों की प्रवृत्ति और साझी नियति बन चुका है, वह दौर खत्म होगा और उत्तर प्रदेश विकास की नयी गाथा लिखने में सक्षम हो सकेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे फोर लेन कैरेज वे है इसके सिक्स लेन विकास की संभावना है। इसमें 49 किलोमीटर पर फूड कोर्ट, पेट्रोल पम्प और टायलेट आदि की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह हेल्पलाइन, सीसीटीवी और एम्बुलेंस की सुविधा से बाकायदा लैस रहेगा। ई वाहनों के लिए पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अब आप बेफिक्र होकर इसके जरिए लखनऊ और दिल्ली तक फर्राटा भर सकेंगे। ◆

आठ साल में बढ़ा धार्मिक पर्यटन

–प्रदीप श्रीवास्तव

धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत समृद्धि वाला राज्य है। इसके उत्तरी एवं पूर्वी भाग में पर्वत मालाएं हैं तो मध्य भाग में मैदान, दक्षिण का विन्ध्याचल क्षेत्र पठारी भू–भाग है। इस तरह हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पर्वतों, मैदानों एवं घाटियों से घिरा हुआ है, या यूँ कहें पूरे, उप–महाद्वीप की दो प्रमुख नदियों गंगा एवं यमुना के किनारे संस्कृतियों और धार्मिक रीतियों का उद्गम स्थल है।

पर्यटन की दृष्टि से देखें तो प्रदेश के पांच बड़े धार्मिक स्थलों, अयोध्या, काशी, नैमिषारण्य, चित्रकूट एवं विन्ध्याचल का कायाकल्प धार्मिक पर्यटकों के लिए अच्छे विकल्प का रूप धारण कर लिया है। इसी प्रदेश से पवित्र पावनी गंगा, यमुना, सरयू के साथ–साथ रामगंगा, शारदा, घाघरा, राप्ती, बेतवा सिन्धु चम्बल गोमती, केन, सोन चंद्रप्रभा आदि न जाने कितनी छोटी–बड़ी नदियाँ बहती हैं।

उत्तर प्रदेश धर्म, संस्कृति एवं पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश है। देवों के देव भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी (बनारस), मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, के साथ–साथ प्रयागराज हिन्दुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ, जहां पर गंगा, यमुना एवं गुप्त सरस्वती का संगम होता है।

इस तरह हम सांकेतिक रूप में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है। वास्तव में देखें तो वास्तु, चमत्कार एवं इतिहास से परिपूर्ण है यह प्रदेश। कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों एवं मंदिरों का गढ़ है उत्तर प्रदेश।

पर्यटन देश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण कारक है, इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि दुनिया के लगभग डेढ़ सौ देशों में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले पांच कारकों में से एक पर्यटन भी है। जो दूर–दराज के क्षेत्रों में रोजगार सृजन का माध्यम है। प्राचीन काल से ही हमारें यहाँ तीर्थाटन या धार्मिक पर्यटन की परम्परा रही है। थोड़ा पीछे जाएं तो पता चलता है कि पहले लोग पैदल या अन्य साधनों से सैकड़ों किलोमीटर चलकर तीर्थाटन किया करते थे। समय बदला, साधन बदले, लोगों की आवश्यकताएं बदली, साधन सुलभ हुए तो पर्यटन की धारणा बदली। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में पांच हजार से अधिक छोटे व बड़े धार्मिक स्थल हैं क्योंकि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है।

2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पर्यटन को नई ऊंचाई मिली। आंकड़े बताते हैं कि 2017 में उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटकों की संख्या संख्या 23.7 करोड़ थी, जो राज्य की आबादी (22.7 करोड़) से अधिक थी। उस साल उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की कुल संख्या में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। विदेशी पर्यटकों ने सबसे ज्यादा आगरा का दौरा किया, जबकि घरेलू पर्यटकों की सबसे ज्यादा संख्या प्रयागराज में देखी गई। वर्ष 2016 में, भारत में 161.3 करोड़ घरेलू पर्यटक आए, जिसमें अकेले कर्नाटक की हिस्सेदारी 21 प्रतिशत थी और उसके बाद 13 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ यूपी था। उसी वर्ष, लगभग 2.4 करोड़ विदेशी भारत आए, जिसमें तमिलनाडु की

हिस्सेदारी 19 प्रतिशत थी और 18.9 प्रतिशत हिस्सेदारी महाराष्ट्र की थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न उपायों के साथ उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। बीते 8 सालों में सरकार ने चित्रकूट और प्रयागराज सहित कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। इसका सीधा असर प्रदेश के पर्यटन आंकड़ों पर देखने को मिला है। जहां साल 2017 में लगभग 24 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश आए थे वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर लगभग 65 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी पिछले 8 वर्षों में प्रदेश ने 41 करोड़ पर्यटकों की वृद्धि दर्ज की है। इस आंकड़े में बढ़ोतरी का सबसे अहम् योगदान प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास का रहा है।

उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व वाले स्थलों को आपस में जोड़ने वाले मार्गों के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए 4,560 करोड़ रुपये की विशाल योजना पूरी करने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 272 कार्यों को वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा।

उधर केंद्र सरकार की 'स्वदेश दर्शन–2' योजना के तहत नैमिषारण्य, प्रयागराज और महोबा को चुना गया है। नैमिषारण्य और प्रयागराज के विकास के लिए धनराशि स्वीकृत हो चुकी है, जबकि महोबा के लिए शीघ्र स्वीकृति मिलने की संभावना है। प्रयागराज में कुंभ नगरी के रूप में इसकी पहचान और अधिक मजबूत होगी, जबकि नैमिषारण्य को आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे पर्यटन विकास के कार्यों का सकारात्मक प्रभाव साफ नजर आ रहा है। धार्मिक पर्यटन से लेकर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास तक, राज्य ग्लोबल टूरिज्म हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उधर केंद्रीय बजट 2025–26 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ 50 पर्यटन स्थलों के विकास की घोषणा की गई है। इसमें भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों के विकास पर विशेष जोर है। इसमें उत्तर प्रदेश को विशेष लाभ मिला है। बौद्ध सर्किट में कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती, सारनाथ, कपिलवस्तु, कौशांबी जैसे स्थल शामिल हैं। भगवान बुद्ध ने तप, ज्ञान, उपदेश, महानिर्वाण के लिए उत्तर प्रदेश को चुना था, जिससे यह बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल बन गया है। सरकार ने बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए विश्राम गृह, सड़कों का नवीनीकरण, अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और डिजिटल गाइड सिस्टम जैसी योजनाएं बनाई हैं, जिससे देश–विदेश के पर्यटकों को यहां आने में अधिक सुविधा मिले।

पर्यटन विकास के कारण उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर होटलों, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, गाइड सेवाओं, हस्तशिल्प और लोकल बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है। विशेष रूप से महिला उद्यमियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी प्रोत्साहित कर रही है, जिससे लोकल हैंडीक्राफ्ट, बनारसी साड़ी, पीतल कला और लकड़ी की कारीगरी को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल रही है।

अब उत्तर प्रदेश केवल धार्मिक पर्यटन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पर्यटन हब बन चुका है। प्रयागराज संगम, चित्रकूट, कुशीनगर और अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को नई पहचान दिलाने के लिए सरकार द्वारा व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। पर्यटन के बढ़ते रुझान और सरकार की नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश में होटल, गाइड, ट्रांसपोर्ट, हस्तशिल्प और अन्य स्थानीय व्यवसायों को जबरदस्त लाभ मिला है।

प्रदेश सरकार अब इसी तर्ज पर पश्चिमी यूपी के जिलों में पर्यटन को बढ़ाने और पर्यटकों का रुख इन जिलों की तरफ करने के लिए यहां के धार्मिक स्थलों पर 300 करोड़ खर्च करने जा रही है। पर्यटन विभाग पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर, शुकतीर्थ और माँ शाकंभरी धाम जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों को पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े धार्मिक पर्यटन स्थलों के तौर पर विकसित कर रही है।

इसके अलावा पूर्वांचल के कई जिलों में भगवान बुद्ध से जुड़े कई बड़े धार्मिक स्थल हैं। इन्हें बौद्ध सर्किट के तौर पर तैयार कर वहां के टूरिज्म को बढ़ाया जा रहा है। ठीक उसी तरह हापुड़, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे जिलों में स्थित बड़े धार्मिक स्थलों के पास पर्यटन सुविधाओं को विकसित कर इसे धार्मिक टूरिज्म से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इन तीनों जिलों में स्थित बड़े धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 28 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस पर कुल 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि गढ़मुक्तेश्वर, शुकतीर्थ और माँ शाकंभरी धाम का अपने जिलों के साथ आसपास के जिलों में काफी बड़ा धार्मिक महत्व है पर प्रदेश के बाकी जिलों व अन्य प्रदेशों में इसको लेकर लोगों के बीच में जानकारी का अभाव है। साथ ही इन बड़े धार्मिक स्थलों के पास बेसिक एमेनिटीज वी रोड सहित कई सुविधाओं की कमी होने के कारण यह पर्यटन की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। पर्यटन विभाग इन्हीं सब सुविधाओं को विकसित कर इन तीनों बड़े धार्मिक स्थलों को प्रदेश के धार्मिक पर्यटन से जोड़कर उन्हें विकसित करने का काम शुरू किया है।

सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी के धाम को प्रमुखता से विकसित किया जा रहा है। लगभग 101 करोड़ रुपए की धनराशि से शाकंभरी देवी धाम और आसपास पर्यटन सुविधाएं विकसित की जा रहीं हैं। यहां मुख्य रूप से प्रवेश द्वार, लैंडस्केपिंग, फुटपाथ, म्यूरल्स स्कल्पचर, वाटर फाउंटेन, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर (टीएफसी), मल्टी लेवल पार्किंग, ओपन थिएटर, राही पर्यटक आवास गृह आदि बनाए जाएंगे।

वहीं मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ में लगभग 79.41 करोड़ रुपए से पर्यटक सुविधाएं विकसित करने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें गंगा घाट के सौंदर्यीकरण का काम, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर (टीएफसी), पार्किंग, मुख्य मार्गों पर कलाकृतियां, लैंडस्केपिंग एवं म्यूरल, साइनेज, पूर्व में निर्मित पार्किंग आदि का जीर्णोद्धार, लाइट एंड साउंड शो, श्रीमद् भागवत कथा केंद्र का निर्माण सहित अन्य कार्य होंगे।

दूसरी तरफ हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में लगभग 111 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से पर्यटन सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसमें मल्टीलेवल पार्किंग एवं प्रवेश द्वार, समेकित पर्यटन सुविधाओं का सृजन एवं पर्यटन विकास, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर/मल्टीकल्चरल हब का पर्यटन विकास, वीआईपी घाट पर पर्यटन सुविधाओं सहित कई अन्य कार्य कराए जाएंगे। ◆

मो. : 870721113

आत्मनिर्भर होते किसान

—अजय श्रीवास्तव

किसानों की आय बढ़ाने को लेकर कई ऐतिहासिक पहल की गई है। इसमें भविष्य की जरूरतों का ख्याल रखते हुए पूर्वानुमानों पर आधारित तकनीक विकसित कर वर्तमान को पटरी पर लाना महत्वपूर्ण है।

योगी सरकार किसानों, युवाओं समेत समाज के लगभग हर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से कदमताल कर रही है। विशेषकर खेती—किसानी में आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने की मंशा के साथ ऐसी योजनाओं के कुछ ताजा उदाहरण यहां दिए जा रहे हैं—

वेदर स्टेशन से किसानों को मिलेगा मौसम पूर्वानुमान

योगी सरकार किसानों को मौसम की मार से बचाने के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का विस्तार अब तेजी से गांव—गांव तक करने जा रही है। क्लाइमेट चेंज और फसलों पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चिंता प्रकट करते रहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की मंशानुरुप कृषि और आपदा विभाग अब मिलकर काम करेंगे। इस कड़ी में सभी तहसीलों में दो स्थानों पर जहां आटोमेटिक वेदर स्टेशन (एडब्ल्यूएस) स्थापित किए जा रहे हैं वहीं हर ब्लाक में चार स्थानों पर आटोमेटिक रेन गेज (एआरजी) भी लगाए जा रहे हैं।

राज्य में 132 एआरजी और 68 एडब्ल्यूएस पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। इनकी संख्या को और बढ़ाया जा रहा है। एडब्ल्यूएस से मौसम का पूर्वानुमान बताया जाएगा तो एआरजी से वर्षा मापने में सहयोग मिलेगा। मौसम की सटीक जानकारी मिल जाने पर किसान खेती को लेकर अपनी योजना बना सकेंगे। मालूम हो कि, अचानक बदले मौसम के चलते खेती में समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन ताजा पहल से वर्षा का क्या हाल रहेगा, शीत लहर कब पड़ेगी आदि की जानकारी पहले मिल सकेगी। हवा की गति क्या होगी, इसके बारे में भी किसान जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

सीड पार्क बनेंगे, किसान होंगे लाभान्वित, मिलेगा रोजगार

योगी सरकार उत्तर प्रदेश में पांच सीड पार्क स्थापित करने को तैयार है। इस कदम से बीज उत्पादन के क्षेत्र में अपना प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किए जाने वाले सीड पार्क को राज्य के 5 क्लाइमेटिक जोन में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाना है। इस योजना के तहत पहले सीड पार्क की स्थापना लखनऊ जिले के अटारी स्थित राजकीय कृषि प्रक्षेत्र की 130.63 एकड़ भूमि पर की जाएगी, जिस पर 266.70 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय होगा। पांच सीड पार्कों की स्थापना से 6000 प्रत्यक्ष एवं 15,000 अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित होंगे।

सीड पार्क के जरिए बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग, भंडारण, स्पीड ब्रीडिंग व हाइब्रिड लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी,

तराई, मध्य, बुंदेलखंड एवं पूर्वी जोन में कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुरूप सीड पार्क स्थापित किए जाएंगे। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार इन सीड पार्कों में निवेश करने वाले बीज व्यवसायियों को विभिन्न रियायतें प्रदान करेगी। बीज उद्योगों को 30 वर्ष की लीज पर भूमि देंगे, जिसे आवश्यकतानुसार 90 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा। एक सीड पार्क से लगभग 1200 लोगों को प्रत्यक्ष तथा 3000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलना संभव है। साथ ही लगभग 40,000 बीज उत्पादक किसान इन पार्कों से सीधे तौर पर जुड़ेंगे।

किसानों की सुरक्षा और हित में एक और अहम् कदम उठाते हुए योगी सरकार ने राज्य में चल रही गेहूं की खरीद को लेकर गाइडलाइन तय की है। इस कड़ी में आढ़तियों और व्यापारियों पर कड़ी निगरानी रखने की हिदायत शासन ने दी है। खासकर आढ़तियों और निजी व्यापारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर निर्धारित मंडी शुल्क दिए बगैर गेहूं की खरीद की तो न केवल उनसे वसूली होगी बल्कि गैरकानूनी कृत्य पाये जाने पर जेल भी हो सकती है। क्रय कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के मद्देनजर सभी सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों एवं समस्त क्रय संस्थाओं के प्रभारियों को यह निर्देशित किया गया कि गांवों में ग्राम प्रधानों एवं किसानों से सम्पर्क कर किसानों का मोबाइल नम्बर, नाम पता, बिक्री के लिए अनुमानित मात्रा, कटाई की सम्भावित तिथि आदि का विवरण सहित माइक्रोप्लान तैयार कर एवं उन्हें प्रेरित कर त्वरित गति से गेहूं क्रय किया जाये।

योगी सरकार किसानों को मौसम की मार से बचाने के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का विस्तार अब तेजी से गांव–गांव तक करने जा रही है। क्लाइमेट चेंज और फसलों पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चिंता प्रकट करते रहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की मंशानुरुप कृषि और आपदा विभाग अब मिलकर काम करेंगे। इस कड़ी में सभी तहसीलों में दो स्थानों पर जहां आटोमेटिक वेदर स्टेशन (एडब्ल्यूएस) स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं हर ब्लाक में चार स्थानों पर आटोमेटिक रेन गेज (एआरजी) भी लगाए जा रहे हैं।

फिर गेहूं खरीद में बनाया नया कीर्तिमान

उ.प्र. सरकार ने एक बार फिर गेहूं खरीद में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 8 मई तक प्रदेश में 1.73 लाख से अधिक किसानों से 9.26 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो गई। वहीं पिछले वर्ष इस अवधि में लगभग 6.88 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद हुई थी। रबी विपणन वर्ष 2025–26 के लिए कुल 4,46,725 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। अब तक 2,045 करोड़ रुपये से अधिक राशि किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जा चुकी है। रबी विपणन वर्ष 2025–26 सीजन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ◆

मो. : 7052084404

अन्नदाताओं की प्रगति के 8 साल

–सियाराम पांडेय 'शांत'

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में यह साबित किया है कि प्रबल इच्छाशक्ति और मन में सेवाभाव हो तो हर क्षण कीमती होता है। सत्ता में आने के बाद लक्ष्य निर्धारण और योजनाओं के क्रियान्वयन की दशा–दिशा ठीक हो तो समग्र विकास के द्वार सहज ही खुल जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए पिछले 8 साल बेहद कल्याणकारी रहे हैं। इस अवधि में न केवल उनकी आय में इजाफा हुआ है बल्कि परेशानियों के दौर में भी सरकार हर क्षण उनके साथ खड़ी नजर आई है। किसानों से किए गए अपने चुनावी वादों को न केवल उसने बखूबी पूरा किया है, बल्कि जातिवादी राजनीति के विलक्षण दौर में उसने प्रदेश के विकास के लिए जिन चार विशेष जातियों का चयन किया है, उसमें युवा, किसान, मजदूर और महिलाएं शामिल हैं। इसे सरकार की दूरदर्शिता नहीं तो और क्या कहा जाएगा?

वर्ष 2017 में सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही लघु एवं सीमांत किसानों के 36 हजार करोड़ रुपये का ऋणमोचन एक झटके में कर दिया था। इस फैसले ने किसानों को तो बड़ी राहत दी ही, कृषि क्षेत्र में सुधार की राह भी आसान की। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2016–17 में उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन जहां 557 लाख मीट्रिक टन था, वहीं वर्ष 2023–24 में बढ़कर यह 669 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया था। खाद्यान्न उत्पादन में इतनी बड़ी वृद्धि इस बात की द्योतक है कि सुविधाएं बेकार नहीं जातीं। वे अपना असर दिखा कर ही रहती हैं। सरकार ने किसानों का विश्वास जीता और किसानों ने पूरे प्रदेश का।

'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' के तहत उत्तर प्रदेश के 2.61 करोड़ से अधिक किसानों को 80,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि सीधे उनके खाते में मिली है। इस प्रदेश में 40 साल से अर्जुन सहायक, बाणसागर और सरयू नहर जैसी परियोजनाएं लंबित थीं लेकिन केंद्र और उत्तरप्रदेश की डबल इंजन सरकार ने न केवल लगकर उसे पूरा कराया बल्कि 23 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा के लाभ से जोड़ने का भी काम किया। हर गांव तालाब अभियान चलाकर, अमृत सरोवरों के निर्माण कराकर न केवल प्रदेश की कृषि भूमि के सिंचन में मदद की बल्कि भूगर्भ जल के स्तर को बरकरार रखने का भी काम

किया। कृषि विज्ञान केंद्र, नए कृषि विश्वविद्यालय और टेक्नोलॉजी के उपयोग ने भी किसानों के उत्साह और सहूलियतों को पंख लगाए। यही वजह है कि धान, गेहूं, दलहन और श्री अन्न (मिलेट्स) उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में अपना नाम दर्ज करा सका। सरकार ने किसानों को उन्नत कृषि तकनीक से जोड़ा, जिससे उनकी उपज की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। वर्ष 2008–09 से वर्ष 2017 तक गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपये चीनी मिलों पर बकाया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्राथमिकता से इसे चुकता किया और किसी भी चीनी मिल को बंद नहीं होने दिया। अलबत्ते उत्तर प्रदेश में 3 नई चीनी मिलों की स्थापना भी की। 6 बंद चीनी मिलों का पुनर्संचालन भी कराया। इस अवधि में सूबे की 38 चीनी मिलों का विस्तार भी किया गया। कहना न होगा कि वर्ष 2017 से अब तक 2.80 लाख करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान कराया जा चुका है। पिछली सरकारों के 22 वर्षों के भुगतान पर अगर गौर करें तो यह राशि 60 हजार करोड़ रुपये से कहीं अधिक बैठती है।

वर्ष 2017 में सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही लघु एवं सीमांत किसानों के 36 हजार करोड़ रुपये का ऋणमोचन एक झटके में कर दिया था। इस फैसले ने किसानों को तो बड़ी राहत दी ही, कृषि क्षेत्र में सुधार की राह भी आसान की।

गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिहाज से सरकार ने चीनी मिलों में एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के गठन से पूर्व तक जहां प्रदेश में 42 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होता था, वहीं अब यह बढ़कर 177 करोड़ लीटर हो गया है। इससे प्रदेश के गन्ना उत्पादक तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के सरकार के प्रयासों को भी गति मिली है। विगत 8 साल में चलाई गई सरकारी योजनाओं से किसान तो खुशहाल हुए ही हैं, उत्तर प्रदेश भी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का मजबूत इंजन बन गया है। उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में सरकार ने व्यापक बदलाव किए हैं। हर गांव सड़क और संपर्क मार्ग से जुड़ा है।मंडी और हाट–बाजार से जुड़ा है। खाद्यान्नों के वितरण में अब बिचौलियों की भूमिका न के बराबर रह गई है।इससे किसान भी सुखी हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी सुधरी है। गन्ना किसानों के लिए किए गए सुधार, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने उत्तर प्रदेश को कृषि क्षेत्र में नए मुकाम पर पहुंचा दिया है।

वैसे भी उत्तर प्रदेश के किसानों की प्रगति की जो नई इबारत लिखी जा रही है, उससे राज्य में कृषि उत्पादन में साल–दर–साल रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के साथ–साथ सरकार जैविक खेती, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और मंडी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर भी ध्यान दे रही है। इन योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों को मिल रहा है।

वर्ष 2016–17 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 557 लाख मीट्रिक टन था, वहीं 2023–24 में यह बढ़कर 669 लाख मीट्रिक टन हो गया है। खाद्यान्न उत्पादकता में भी सुधार का आलम यह है कि अब वह 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 31 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है। तिलहन उत्पादन में 128 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 2016–17 में तिलहन का उत्पादन 12.40 लाख मीट्रिक टन था, वह 2023–24 में 28.31 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। 400 लाख टन से अधिक फल और सब्जियों का उत्पादन कर उत्तर प्रदेश ने देश में अग्रणी स्थिति बना ली है। सरकार द्वारा किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की जिस तरह प्रेरणा दी जा रही है, उसका असर यह रहा है कि 49 जिलों में 85,710 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती होने लगी है। बुंदेलखंड के सभी जिलों में 23,500 हेक्टेयर क्षेत्र में गौ आधारित प्राकृतिक खेती शुरू की गई है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 66 लाख क्विंटल बीज, 95 लाख मीट्रिक टन उर्वरक, 8.50 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटा है जिससे किसान अपनी जमीन की सेहत का ख्याल और उसकी उर्वरता को बरकरार रख सकें। किसानों की आय

बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सरकारी योजनाएं मील के पत्थर की भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 58.07 लाख किसानों को 47,535 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 76,189 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे सिंचाई लागत घटने से किसान राहत की सांस ले पा रहे हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 63 हजार किसानों को सहायता दी गई है। किसान आधुनिक खेती से जुड़ सकें और अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर सकें, इस निमित्त सरकार ने राज्य में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया है। कृषि उत्पादक संगठन और कृषि स्नातकों को ड्रोन के उपयोग के लिए 40–50 प्रतिशत तक सरकार अनुदान दे रही है। कृषि विपणन को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए मंडी व्यवस्था को डिजिटल बनाया गया है। प्रदेश की 125 मंडियों में जनवरी 2025 तक 6,999 करोड़ रुपये का डिजिटल व्यापार हुआ है। किसानों को दिक्कत न हो, इस निमित्त सरकार ने 922 ई–लाइसेंस जारी किए हैं। 4.18 करोड़ से अधिक ऑनलाइन पर्चियां निर्गत की गई हैं। राज्य की 27 नई मंडियों का आधुनिकीकरण किया गया और 85 ग्रामीण हाट बाजार बनाए गए हैं। मंडियों में डिजिटल पेमेंट और प्री–अराइवल ई–पास की सुविधा शुरू की गई है।

सरकार किसानों को तकनीकी सुविधाएं देने के लिए 'यूपी मंडी भाव मोबाइल ऐप' चला रही है, जिससे किसान बाजार भाव और मौसम की जानकारी से हर क्षण अपडेट रहें। लखनऊ में 49 करोड़ रुपये की लागत से 'किसान एग्री मॉल' का निर्माण किया जा रहा है जो अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि इससे किसान आधुनिक सुविधाएं पा सकेंगे। योगी सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। सीडलिंग उत्पादन से 60 हजार महिलाओं को रोजगार मिला है। महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि कार्यों में जोड़ा गया है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं।

पिछले आठ वर्षों में 878,192 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरित किया गया है। किसानों को सम्मानित करने और उनके लिए नई योजनाएं शुरू करने में भी योगी सरकार का कोई सानी नहीं है। पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत बड़ी तादाद में किसानों को ट्रैक्टर प्रदान किए गए हैं।

Regenerative practices, balance nutrition and
10 lakh acres covered under Zero Tillage
50+ partnerships with Govt and Research Institutes
2 lakh+ Climate Smart Women Farmers, Krishi Sakhis, Wom

किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाना और लखनऊ में 251 करोड़ रुपये की लागत से चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क बनाने की घोषणा यह बताने के लिए काफी है कि सरकार कृषकों के समग्र विकास को लेकर वाकई बहुत गंभीर है।

दिसंबर 2024 तक 60.48 लाख किसान पहचान पत्र जारी कर सरकार ने प्रदेश के किसानों को आत्म गौरव से जोड़ने की दिशा में अहम् भूमिका निभाई है। बाढ़ सुरक्षा के

लिए 1,551 परियोजनाएं शुरू कर योगी आदित्यनाथ सरकार ने 32.87 लाख हेक्टेयर भूमि को न केवल बाढ़ से बचाया है बल्कि करोड़ों किसानों को बड़ी राहत भी दी है।

योगी सरकार लगातार कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रही है। राज्य में खेती को अधिक लाभदायक और टिकाऊ बनाने के लिए नई तकनीकों और योजनाओं को लागू किया जा रहा है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें नई तकनीकों से जोड़ने के लिए सरकार कई और बड़े कदम उठाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में किसान अब आत्मनिर्भर हो रहे हैं और उनकी आय में लगातार वृद्धि हो रही है। आने वाले वर्षों में सरकार खेती–किसानी को बेहतर बनाने के लिए और भी नई योजनाएं शुरू करने की दिशा में कार्य कर रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब यहां के किसान ड्रोन तकनीक से फसल सुरक्षा कर रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ समेत छह जिलों में ड्रोन से नैनो यूरिया और कीटनाशकों का छिड़काव शुरू हो गया है। इस पहल से एक घंटे में तीन से 12 एकड़ तक के क्षेत्रफल में फसलों पर प्रभावी ढंग से छिड़काव सम्भव हो पा रहा है। इससे न केवल फसल उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों को कम समय में अधिक लाभ मिलेगा। योगी सरकार आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) जैसी योजनाओं के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयास कर रही है।

AGRO TECH INDIA

प्रदेश में कुल नौ ड्रोन प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। गोरखपुर, बहराइच और मुजफ्फरनगर में दो–दो और लखनऊ, गाजियाबाद और कानपुर नगर में एक–एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। ड्रोन के माध्यम से किसानों को टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। स्मार्ट एग्रीकल्चर की ओर यूपी सरकार का यह मजबूत कदम है। ड्रोन तकनीक के इस नवाचार से उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित यह पहल आने वाले समय में किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है।

क्रय केंद्रों की स्थापना और साल–दर–साल फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाकर सरकार किसानों की अर्थ व्यवस्था को बढ़ाने के जो प्रयास कर रही है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए, कम है।

वैसे भी सरकार को पता है कि कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है,अगर इसे साध लिया जाए, दुरुस्त कर लिया जाए तो विकास का पहिया स्वतः ही गांवों से शहरों की ओर दौड़ने लगेगा। गांव सम्पन्न होंगे तो देर–सबेर इसका प्रभाव शहरी और नगरीय विकास पर भी पड़ेगा। प्रदेश के समग्र विकास के लिए इससे उम्दा स्थिति दूसरी हो भी नहीं सकती। ◆

मो. : 7459998968

अन्नदाता को नमन

किसान कल्याण मिशन

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से

2.86 करोड़+ किसानों को

₹80,000 करोड़ हस्तांतरित

₹36,359 करोड़ से 94 लाख+ किसानों का ऋण मोचन

खुशहाल किसान

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : 25 लाख+ कृषकों के 20 हेक्टेयर+ कृषि क्षेत्र का बीमा
- पी.एम. कुसुम योजना : किसानों को 75,000+ सोलर पंपों का आवंटन
- 49 जनपदों के 85,710 हेक्टेयर में गौ आधारित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम
- कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना
- गन्ना किसानों को रिकॉर्ड ₹2,73,000 करोड़+ गन्ना मूल्य का भुगतान
- चांगीपुर (बिजनौर), पिपराइच (गोरखपुर) एवं मुंडेरवा (बस्ती) में नई चीनी मील की स्थापना
- 6 चीनी मिलों का पुनर्संचालन, 36 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण
- गन्ना मूल्य : ₹315 से बढ़कर ₹370 प्रति कुंतल, 1,10,600 टीसीडी अतिरिक्त पेराई क्षमता
- खाद्यान्न उत्पादन 669 लाख मीट्रिक टन/वर्ष तथा फल एवं सब्जी 400 लाख टन/वर्ष
- निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु 7,713 आश्रय स्थलों में 12.50 लाख गोवंश संरक्षित
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना : 2.60 लाख किसानों को कार्ड वितरण
- 976 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण, 48.32 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता में वृद्धि
- केन-बेतवा लिंक परियोजना की स्थापना हेतु ₹5,122 करोड़ का प्रावधान

काम दमदार - डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

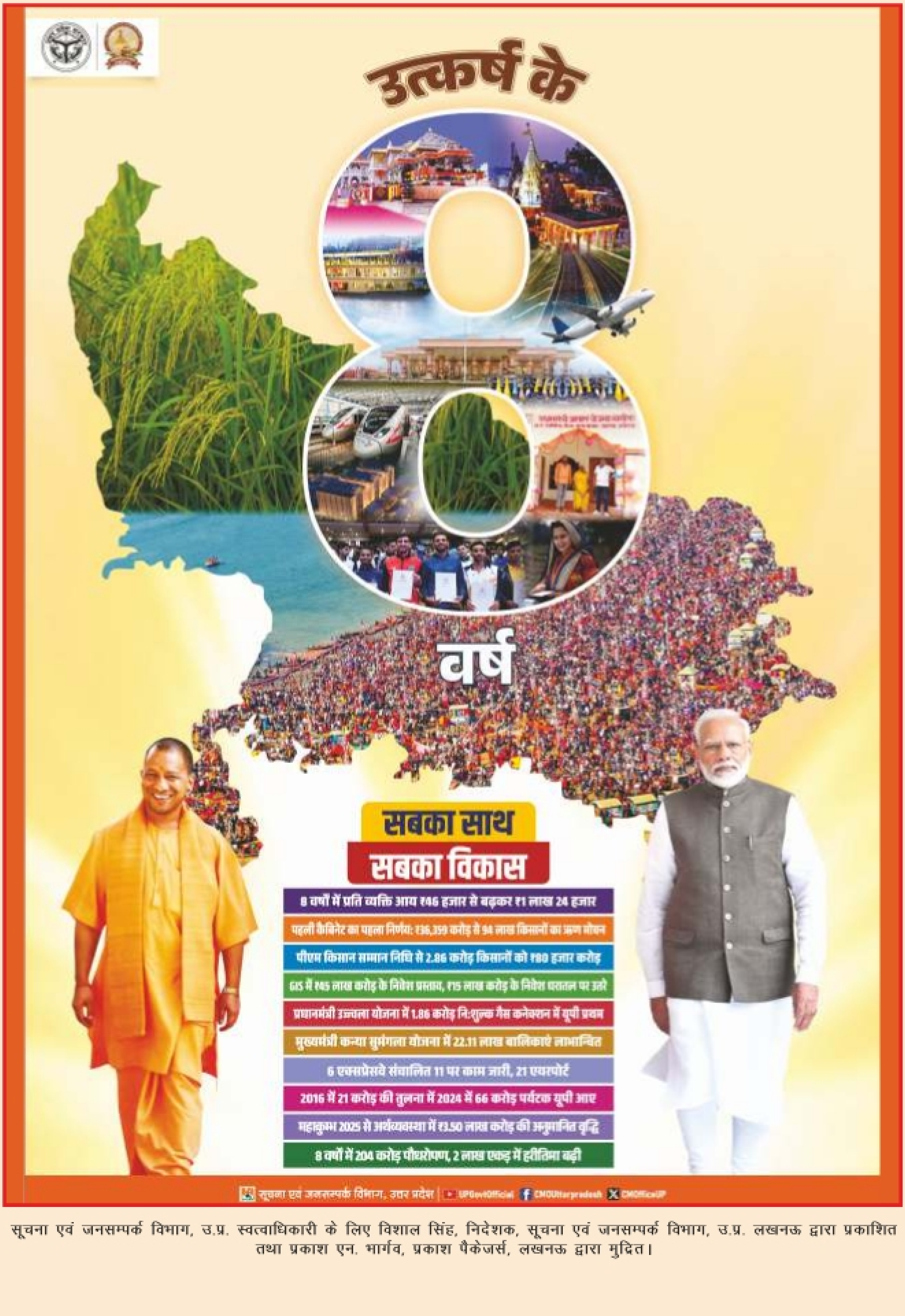

उत्कर्ष के 8 वर्ष

सबका साथ सबका विकास

- 8 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय ₹46 हजार से बढ़कर ₹1 लाख 24 हजार
- पहली कैबिनेट का पहला निर्णय: ₹36,359 करोड़ से 94 लाख किसानों का ऋण मोचन
- पीएम किसान सम्मान निधि से 2.86 करोड़ किसानों को ₹80 हजार करोड़
- GIS में ₹45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, ₹15 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतरे
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1.86 करोड़ नि:शुल्क गैस कनेक्शन में यूपी प्रथम
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 22.11 लाख बालिकाएं लाभान्वित
- 6 एक्सप्रेसवे संचालित 11 पर काम जारी, 21 एयरपोर्ट
- 2016 में 21 करोड़ की तुलना में 2024 में 66 करोड़ पर्यटक यूपी आए
- महाकुंभ 2025 से अर्थव्यवस्था में ₹3.50 लाख करोड़ की अनुमानित वृद्धि
- 8 वर्षों में 204 करोड़ पौधरोपण, 2 लाख एकड़ में हरीतिमा बढ़ी

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश | UPGovtOfficial | CMOUttarpradesh | CMOfficeUP

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. स्वत्वाधिकारी के लिए विशाल सिंह, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ द्वारा प्रकाशित
तथा प्रकाश एन. भार्गव, प्रकाश पैकेजर्स, लखनऊ द्वारा मुद्रित।